राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 2 ■ अंक 11 ■ फरवरी-मार्च 2019 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 36

आत्मघाती है राष्ट्रीयता के ज्वार को बाँधने की कोशिश

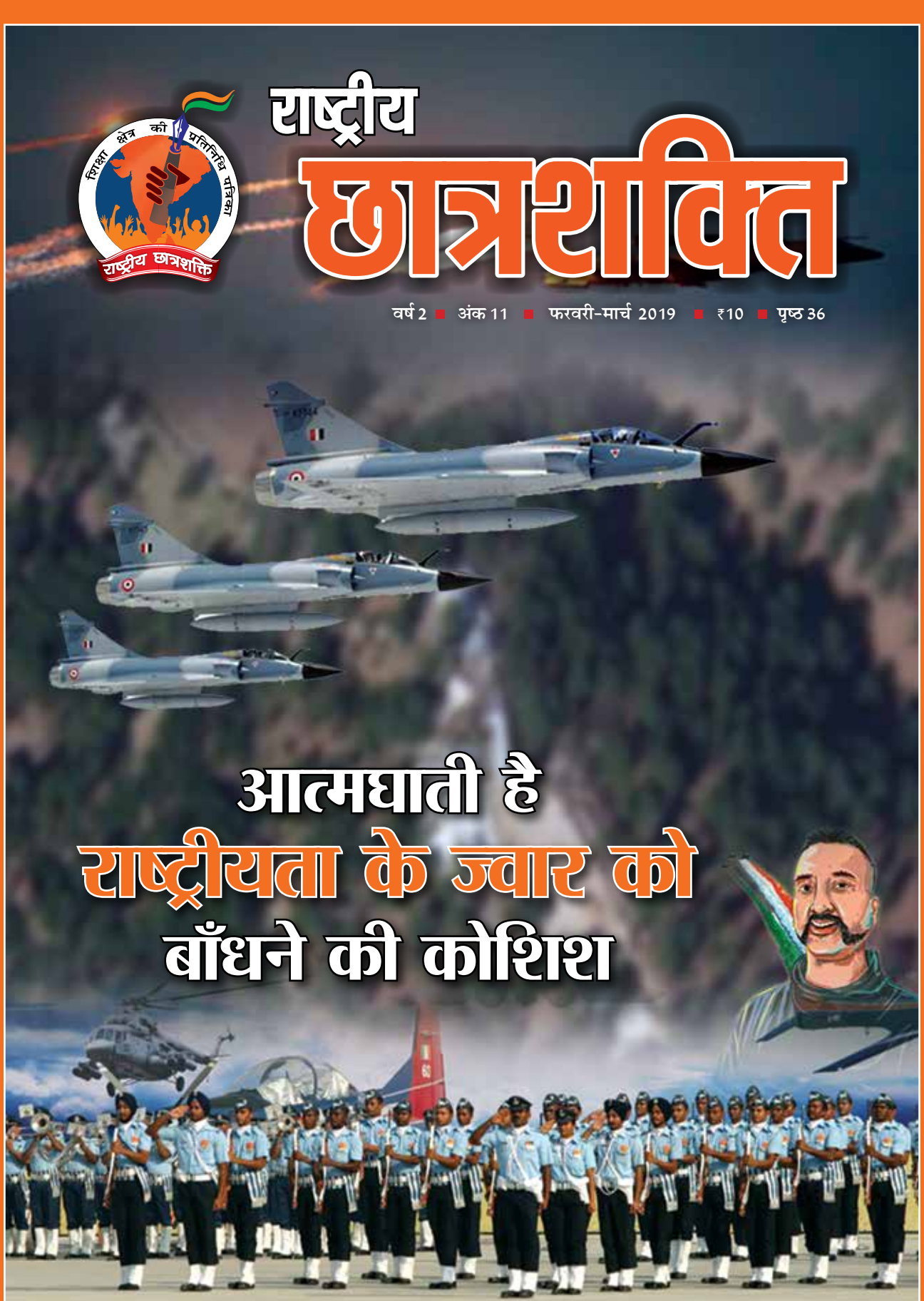

परिषद् गतिविधियां

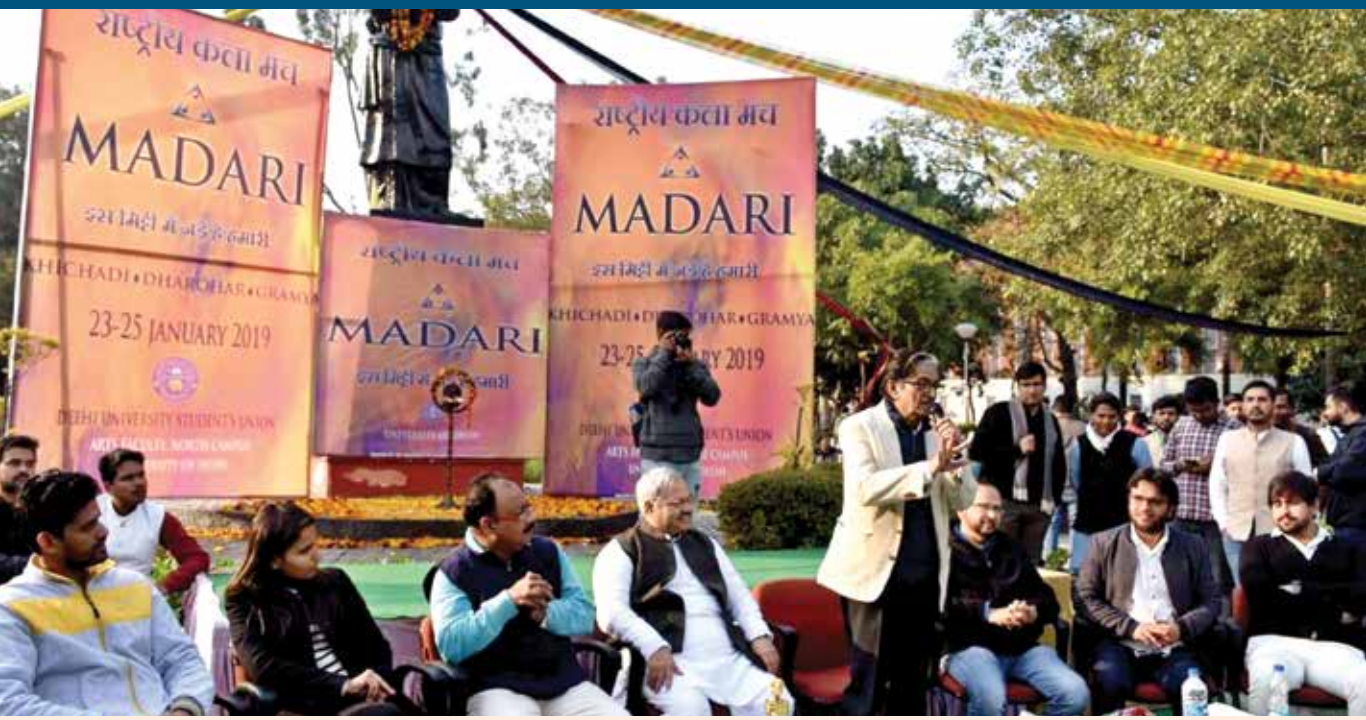

दिल्ली : राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित मदारी महोत्सव के दौरान अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, प्रख्यात नाटककार दयाप्रकाश सिन्हा, लेखक नरेश शांडिल्य, कला मंच के संयोजक ध्रुव कांडपाल, डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह व अन्य

गुमला (झारखंड) : अभाविप द्वारा आयोजित जनजाति छात्र जुटान उदघाटन समारोह के दौरान झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, पद्मश्री अशोक भगत, अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन, प्रांत अध्यक्ष प्रो. नाथू गाड़ी व अन्य

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 2, अंक 11
फरवरी–मार्च, 2019

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

05 **आत्मघाती है राष्ट्रीयता के ज्वार को बाँधने की कोशिश**

14 फरवरी को कश्मीर के गोरीपोरा में आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 49 जवानों का बलिदान हुआ। दर्जनों घायल...

संपादकीय	04
पाकपरस्त आतंकियों के आतंक के खिलाफ़ भारत ने छेड़ी निर्णायक जंग	08
शिक्षा ऐसी हो जो मानवता की रक्षा करे : डॉ. एस. सुबैय्या	12
NATIONAL SECURITY AND RAFAEL DEAL	14
कृषि शिक्षा उत्थान पर है सरकार का विशेष जोर : राधामोहन सिंह	16
कुम्भ की शिक्षाओं को संजोए रखें युवा	17
मन से नहीं धन से हैं गरीब,गर्व करें हम आदिवासी हैं : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू	19
NRC : A GLANCE	21
राष्ट्रीय कला मंच के मदारी महोत्सव में दिखी लोक कला की झलक	23
धर्मपथ और शांतिपथ के चौराहे पर गांधी	24
केंद्र सरकार के अध्यादेश से पीड़ितों को मिला न्याय : अभाविप	25
भारत जैसी पारिवारिक संरचना मुझे कहीं नहीं दिखी : माधुरी सहस्त्रबुद्धे	26
परिवर्तन की राह पर पश्चिम बंगाल	28
75 YEARS OF HOISTING TIRANGA IN ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS – SAGA OF GUTS AND GLORY	31
परिचर्चा : पुलवामा हमला और भारत की कार्रवाई पर विपक्ष की प्रतिक्रिया कितना उचित?	33

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

जम्मू कश्मीर विश्व कूटनीति की चौसर पर हमेशा से रहा है। उसकी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति ही उसे महत्वपूर्ण बनाती है और दुनिया की आंख का कांटा भी। जिसने भी उसके इस महत्व को समझा, उसने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। जिसके नियंत्रण में यह रहा, दुनिया में उसकी हैसियत बडी बनी रही। इसलिये इस भू-भाग पर नियंत्रण की इच्छा ने इस सुरम्य प्रदेश को युद्ध क्षेत्र बनाये रखा।

प्राचीन इतिहास में प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से भारत का भाग होने के कारण इसका लाभ भारत को मिला। भारत ने अपने स्वभाव के अनुकूल इसका लाभ व्यापार को बढ़ाने औऱ सांस्कृतिक विस्तार करने के लिये किया। इसी के रास्ते बौद्ध मत चीन सहित अनेक देशों में पहुंचा और सम्राट अशोक और ललितादित्य जैसे शासकों का साम्राज्य भी।

तेरहवीं शताब्दी में यहां इस्लाम का आगमन हुआ। यह कश्मीर के इतिहास का प्रारंभ नहीं है, जैसा आज बताने की कोशिश होती है। यह उसके हजारों वर्ष के लंबे इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत है जो आने वाले इतिहास के लिये आधारभूमि तैयार करता है। कल्हण ने राजतरंगिणी में इसका विस्तार से वर्णन किया है।

शास्त्रार्थ से सत्य तक पहुंचने और सभी मार्गों से ईश्वर तक पहुंचने की संभावना के लिये इस्लाम में कोई स्थान नहीं हैं वहीं तलवार के दम पर पूजा पद्धति बदलने के लिये विवश करने की घटनाएं कश्मीर के लिये अकल्पनीय हैं। इसलिये आगे का इतिहास संघर्ष का इतिहास है जहाँ भारतीय मूल्य एवं परम्पराओं और एक अजनबी सभ्यता के बीच ठनी हुई है।

एक ओर एक ऐसी दुनिया बनाने की चाहत है जहां विविधता के लिये कोई स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर निजी स्वार्थों में लिप्त बौने राजनेताओं की वंशबेल हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के प्रारंभिक छः दशकों में इस समस्या को पाला-पोसा और बढ़ाया। सोशल मीडिया के सूरमा जो आज की सत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने भीतर झांक कर देखें तो जम्मू कश्मीर की समस्या का मूल जानना कठिन नहीं है।

महाशक्ति के रूप में उभरता भारत आज उस आत्महीनता को ढोने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये जब भारत शत्रु देश के भीतर घुस कर वार करता है और उसका जांबाज सैनिक पचास साल पुराने विमान से दुनिया में अत्याधुनिक माने जाने वाले अमेरिकी विमान को मार गिराता है तो आज का युवा स्वाभिमानी नेतृत्व के साथ जोश में 'भारत माता की जय' बोल उठता है।

यह नया भारत है जो शत्रु की तोपों का जवाब सफेद कबूतरों से देने का समर्थक नहीं है। वह युद्धोन्मादी नहीं है, लेकिन 'शांति को एक अवसर' देने के नाम पर आतंकियों को बच निकलने देने के लिये भी तैयार नहीं है। स्वतंत्रता के बाद संभवतः यह पहला अवसर है जब पूरा देश उठ खड़ा हुआ है और आतंक के खिलाफ एकजुट है। वर्तमान नेतृत्व युवाओं की इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देकर सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत के निर्माण का पथ प्रशस्त कर सकता है।

भवदीय

संपादक

आत्मघाती है राष्ट्रीयता के ज्वार को बाँधने की कोशिश

14 फरवरी को कश्मीर के गोरीपोरा में आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 49 जवानों का बलिदान हुआ। दर्जनों घायल हैं जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर है। हमला जैश-ए-मुहम्मद के अफजल गुरु स्क्वॉड ने किया है जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। पहले से रिकॉर्ड किये गये हमलावर आदिल के एक वीडियो को बाद में जैश ने जारी कर हमले की जिम्मेदारी भी ली।

सरकार के सामने यह घटना चुनौती के रूप में आयी है जबकि आम चुनाव सिर्फ दो महीने दूर हैं। पिछले कुछ समय से आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को एक सफलता के रूप में देख रहा देश इस घटना से स्तब्ध है। ऑपरेशन ऑल-आउट के चलते जिस तरह से घाटी में सक्रिय सभी आतंकी समूह बैकफुट पर आ गये थे उससे यह आशंका तो थी कि वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। सरकार को चुनौती देने से अधिक उनके अपने कैडर के खोते आत्मविश्वास को बनाये रखने के लिये यह जरूरी था। जिस तरह से सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया कर रहे थे उसके चलते उन्हें अपने परंपरागत ठिकानों और समर्थकों का भी साथ मिलना कम होता जा रहा था।

हाल ही में इशरत की जिस दरिंदगी से उन्होंने हत्या की और उसका वीडियो वायरल किया उससे उनकी निराशा की भी झलक मिलती है और अपने ही साथियों और समर्थकों को धमकाने की कोशिश की भी। संक्षेप में, साम-दाम-भय और भेद द्वारा अपने निरंतर सिकुड़ते जा रहे आधार को बचाये रखने की कोशिश भी इसमें शामिल है। इसमें अगर कुछ अलग है तो वह है किसी कश्मीरी आतंकी का आत्मघाती के रूप में इस्तेमाल। अफगानिस्तान और सीरिया में तो यह होता रहा है किन्तु कश्मीर घाटी में यह अपवाद ही है। खबरें यह भी आ रही

हैं कि जैश ने आदिल के अलावा चार और आतंकियों को भी आत्मघाती हमले के लिये तैयार किया है। आगे देखना होगा कि यह घटना अपवाद ही रहेगी अथवा कश्मीर में आतंकवाद एक नये दौर में प्रवेश कर गया है।

घटना के समाचार आने के ठीक बाद जो प्रतिक्रियाएं राजनैतिक दलों के द्वारा आयीं वे स्वागत योग्य तो नहीं ही थीं। यह जरूर है कि देश में बने माहौल को देखते हुए उनमें बाद में सुधार किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया वहीं केन्द्र पर हमले का कोई मौका नहीं चूकने वाली शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने हमले रोकने के लिये मोदी सरकार की पूरी तैयारी न होने की बात कही। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो मंत्री बने नवजोत सिद्धू ने एक बार फिर अपने बेतुके बोल बोले।

पूरे मामले में जो सबसे चिंताजनक पहलू है वह है इस माहौल में भी जश्न मनाने की घटनाओं का सामने आना। इससे भी आगे, जो लोग इससे खुश हुए, उन्होंने अपनी खुशी को सोशल मीडिया पर जाहिर भी किया। ऐसी घटनाएं पूरे देश में सामने आयीं। एक राष्ट्रीय चैनल की समाचार उपसंपादक द्वारा भी आपत्तिजनक ट्वीट किया गया। इन घटनाओं को देख कर लगता है कि मोदी के नेतृत्व को लेकर जो राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अथवा वैचारिक विरोध है वह रंजिश की हद तक पहुंच गया है। मोदी विरोध के लिये वे पुलवामा घटना पर उपजी पूरे देश की संवेदना को ताक पर रख सकते हैं।

जम्मू कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी सहित अनेक स्थानीय राजनैतिक दलों ने घटना की निन्दा की औपचारिकता के बाद देश भर में कश्मीरियों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया अभियान छेड़ दिया। जबकि इनमें से कुछ को छोड कर अधिकांश आधारहीन थीं। जम्मू में सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर से इस संवेदनशील मौके पर भी पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगना सच में चिंताजनक है। इससे कुछ दिन पहले भी जब जम्मू-श्रीनगर हाईवे बर्फबारी के कारण रुक गया था तो कश्मीरी समूह में मौजूद कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगा कर माहौल खराब करने की कोशिश की थी। इससे भड़के कॉलेज विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठी भांजी थी और आनन-फानन में कश्मीरियों को विशेष विमानों द्वारा श्रीनगर पहुंचाया गया था। इससे उपजा गुस्सा ही था जो पुलवामा घटना के बाद ज्यादा तीखे विरोध के रूप में सामने आया और नौबत कर्फ्यू लगाने तक जा पहुंची।

कश्मीर के स्थानीय राजनैतिक दल और कथित सिविल सोसायटी हमेशा की तरह देश की संवेदनाओं से निर्लिप्त बने रहे। उनके नेताओं अथवा प्रतिनिधियों ने जवानों को श्रद्धांजलि देने की भी जरूरत नहीं समझी। खासतौर पर फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, तीनों ही मुख्यमंत्री के रूप में यूनीफाइड कमांड के मुखिया रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में सुरक्षा के मुद्दे पर नीतिगत स्तर पर लिये गये राजनैतिक फैसलों का यह परिणाम है। पिछले सत्तर वर्षों में से अधिकांश समय इन दोनों में से कोई न कोई परिवार राज्य की सत्ता पर काबिज रहा है। आज स्थिति जहां पहुंच गयी है उसके लिये वे ज्यादा जिम्मेदार हैं और इससे वे इनकार नहीं कर सकते।

जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम में शुरुआती दौर की औपचारिक बयानबाजी के बाद अब सभी राजनैतिक दल अपनी पुरानी जमीन पर लौट आये हैं। जल्दी ही देश में आम चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनैतिक दलों के सामने दो प्रकार की चुनौतियां हैं। पहला, देश भक्ति के इस माहौल में विभिन्न राजनैतिक दलों के जाति और क्षेत्र के नाम पर विभाजन जैसे तमाम मुद्दे, जिनके भरोसे वे चुनावी वैतरणी पार करना चाहते थे, परिदृश्य से ओझल हो गये हैं। अब उनकी कोशिश है कि संदेह और भ्रम का कोहरा फैला कर बालाकोट हमले के असर को कम किया जा सके। इतने कम समय में नये मुद्दे तलाश कर उन्हें स्थापित करना उतना ही कठिन है जितना पुराने मुद्दों में फिर से जान डालना।

दूसरा भय है बालाकोट पर हवाई हमला कर एक नायक के रूप में उभरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कद को उतना छोटा करना, जिससे एक-दूसरे के कंधे पर सवार हो कर वे उनसे ऊंचे निकल जायें। गठबंधन के सहयोगियों के बीच कोई भी इस कद का नहीं है कि पुलवामा पश्चात के मोदी के बराबर खड़ा हो आंख में

आंख डाल कर बात कर सके, वहीं कोई भी अपने कंधे पर किसी को सवार होने देने के लिये भी तैयार नहीं है। अपने राजनैतिक हित के लिये भी नहीं। हर कोई सबसे ऊपर रहना चाहता है ताकि चुनाव बाद ऊपर से सीधे कुर्सी पर छलांग लगा सके।

कश्मीर के स्थानीय राजनैतिक दलों, नेशनल कांफ्रेस और पीडीपी का स्टैंड तो जग जाहिर ही है। नेकां नेता फारुख अब्दुल्ला ने तो पुलवामा हमले के बाद सर्वदलीय बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि "यह हमारी गलती नहीं है कि हमला हुआ। यह सरकार की गलती है कि उसने वक्त रहते कश्मीरियों की आवाज और मांगें नहीं सुनी"। क्या वे यह कहना चाहते थे कि यदि कश्मीरियों की आवाज नहीं सुनी जायेगी तो पाकिस्तान के इशारे पर जैश-ए-मुहम्मद उसका बदला लेगा। पिछले साल फारुख अब्दुल्ला ने केन्द्र को चुनौती दी थी कि "कश्मीर में तिरंगा थामने वाला भी नहीं मिलेगा" तो इस बार महबूबा ने इस धमकी को दोहराया। महबूबा सीधे तौर पर अलगाववादी धड़े के साथ खड़ी दिखायी दे रही हैं। केन्द्र द्वारा जमात-ए-इस्लामी पर लगाये गये प्रतिबंध को उन्होंने "हमारे मजहब में दखलंदाजी" बताते हुए "बर्दाश्त न करने" की चेतावनी दी।

पिछले कुछ दशकों में कश्मीर घाटी में जो हालात बने हैं, या कहें कि बना दिये गये हैं, उसमें राजनीति मजहब और अलगाववाद के इर्द-गिर्द घूमती है। केन्द्र को छोटा दिखा कर खुद को ताकतवर साबित करना वहां की राजनीति का पैंतरा है जिसे नजरअंदाज करके पिछले दशक तक दिल्ली ने कामचलाऊ संबंध बनाये रखने की नीति अपनायी। इसके बदले में घाटी के राजनेता भी कश्मीर में अलगाववादी भाषा बोलते थे, जम्मू में सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे और दिल्ली आने पर भारतीय हो जाते थे। इस तरह दोनों का काम चलता रहता था। लेकिन मोदी सरकार के तौर-तरीके इससे अलग हैं और राजनीति के दोहरे पैमाने उसे मंजूर नहीं हैं। यही जम्मू कश्मीर की राजनीति की हालिया समस्या है।

जब पूरा देश देशभक्ति के जज्बे में डूबा है, सेना के ऑपरेशन और उससे मरने वाले आतंकवादियों की संख्या पर सवाल उठा कर विपक्ष इसे झूठा अथवा निरर्थक साबित करना चाहता है। इस अभियान में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, पी. चिदंबरम और दिग्विजय सिंह ही नहीं हैं। ममता बनर्जी, नवजोत सिद्धू, अरविन्द केजरीवाल आदि भी इसमें जुगलबंदी कर रहे हैं। मीडिया का भी एक तबका इस कोरस में शामिल है। कथित सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारवादी भी अपनी पूरी ताकत से इस अभियान में जुटे हैं। भारत में इन्हें कोई सबूत नहीं मिलता तो पाकिस्तानी नेताओं के बयान अथवा विदेशी अखबारों की कतरनें लहराने लगते हैं। महागठबंधन में शामिल नेताओं को लगता है कि उनका यह दांव सफल होने पर देश की राजनीति फिर से उसी जाति और मजहब पर आ टिकेगी, जिसका उन्हें लम्बा तजुर्बा है। उन्हें यह भी भरोसा है कि आज भले ही महागठबंधन में कोई सहमति नहीं बन सकी हो लेकिन सत्ता की गोंद चुनाव जीतने पर उन्हें एक बनाये रखने में सफल होगी।

अगर वे इस समझ पर भरोसा करके चल रहे हैं तो वे गलत हैं। पीढ़ियों की राजनीति के बाद भी उन्होंने भारत और भारतीय चरित्र को समझने की कोशिश नहीं की है। वे नहीं स्वीकार कर सके हैं कि भारतीय समाज की समझ में राष्ट्र किसी "वाद" का नाम नहीं बल्कि जीवनपद्धति का अभिन्न अंग है। यह राष्ट्रीयता का आंदोलन ही था जिसने गांधी और नेहरू को सर-आंखों पर बिठाया था और स्वतंत्र भारत की सत्ता उन्हें सौंप दी थी। यह उनकी देशभक्ति पर विश्वास ही था कि 1962 की पराजय के बाद भी देश ने उनकी गलतियों को माफ कर दिया था और 1967 में नेहरू के उत्तराधिकार को लेकर सामने आयी राजनैतिक कलह के बावजूद कांग्रेस को सत्ता सौंप दी थी।

विपक्ष के महागठबंधन, खास तौर पर राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिये कि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में तत्कालीन विपक्ष और उसके नेता स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या भूमिका ली थी। उस समय विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा हुआ था। इससे न केवल इंदिरा सरकार को कठोर निर्णय लेने में मदद मिली बल्कि विपक्ष की भी प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में आज की कांग्रेस जिस तरह चुनावी लाभ के लिये राष्ट्रीयता के ज्वार को निरर्थक विवाद के तिनकों से बांधने की कोशिश कर रही है वह उसके लिये ही आत्मघाती साबित होगा। ■

पाकपरस्त आतंकियों के आतंक के खिलाफ़ भारत ने छेड़ा निर्णायक जंग

| अभिषेक रंजन |

14 फरवरी 2019 को दोपहर तक़रीबन 3 बजे पुलवामा के लेथपोरा के नजदीक 2500 से भी अधिक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को ले जा रहे 78 वाहनों के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में देश के 49 वीर जवान शहीद हो गए, वही 35 से अधिक जवान बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। अपनी छूट्टियों से वापस जा रहे देश की सुरक्षा करने वाले प्रहरी दुश्मनों के निशाने पर थे। जेहादी आतंकी ने लड़ने की बजाए विस्फोटक से भरी गाड़ी से खुद को उड़ा कर, भारत माता के वीर सपूतों की जान ले ली।

पुलवामा का यह हमला जम्मू - कश्मीर के क्षेत्र में अपने आप में न केवल बड़ा हमला था बल्कि यह आत्मघाती हमला ISIS के लड़ाकों के किये जाने वाले हमलों के तर्ज पर भी था, जो एक नई चुनौती का संकेत दे रहा था। उरी में हुए हमले से उलट इस हमले में बेहद खतरनाक विस्फोटक और आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया जाना दुश्मनों की बदलती रणनीति के संकेत दे रहे थे, जिसका उद्देश्य एक साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा प्रहरियों को निशाना बनाना था। हाल के वर्षों में किसी देश की सेना पर इस तरीके के हमले 2017 में अफ़ग़ानिस्तान में हुए थे। दिग्भ्रमित कश्मीरी युवक की आड़ में किये इस हमले की जिम्मेवारी पाकिस्तान स्थित 'जैश - ए - मोहम्मद' नामक आतंकी संगठन ने ली। हमले के तुरंत बाद पहले से रिकॉर्ड एक वीडियो सामने आया, जिसमें खुद को इस्लाम का प्रचारक बताते हुए आत्मघाती हमलावर ने इस हमले को शुरुआत भर बताया। बताया जाता है कि हमले में शामिल 22 वर्षीय यह आतंकी बीते दो वर्षों में कई बार पुलिस की गिरफ्त में आया लेकिन हर बार वह छूट गया।

पुलवामा हमले के बाद देश भर में जवानों को खोने का दर्द और हमले के जिम्मेवार पाकिस्तान के प्रति गुस्सा राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन सरकार से दुश्मनों को सबक सिखाने की मांग करने लगा। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, इस हमले के बाद देश के सभी कोने के नागरिक शहीदों के परिवार और सेना साथ खड़े थे। घटना से न केवल देश में बल्कि विदेश के कोने - कोने में बसे भारतीय एवं विदेशी मित्र भी हतप्रभ थे, शोकाकुल थे, सरकार के साथ थे और आतंक के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

अपेक्षाएं भी थीं क्योंकि सरकार कड़ी निंदा करने वाली नही, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये सीमापार जाकर भी बदला लेने वाली सरकार है। वही हुआ! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर सेना को अपने हिसाब से कार्रवाई करने की छूट दी। भारत सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तान को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दिया टैग वापस ले लिया तथा पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यापार पर 200 प्रतिशत का कर लगा दिया। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने पाकिस्तान को अलग-थलग करने का प्रण लेते हुए पूरे विश्व के नेताओं को पाकिस्तानी हरकत की न केवल जानकारी दी बल्कि उन्हें अपने भरोसे में लिया। भारत ने मनी लॉन्डरिंग और आतंकी फंडिग पर लगाम कसने वाले वैश्विक संगठन फाइनेंसियल एक्शन टास्क फ़ोर्स ऑन मनी लॉन्डरिंग (FATF) से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की, जिसपर इस संस्था ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाये रखते हुए अक्टूबर

2019 तक का अल्टीमेटम दिया। इस लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद अब आसानी से नही मिल सकेगी।

भारत जहां पाकिस्तान को पूरी दुनिया में घेरने में जुटा था, देश के अन्दर चल रहे उन संगठनों पर भी सरकार ने लगाम कसनी शुरू की, जो कश्मीरी अलगाववाद के प्रतीक और पाकिस्तानी आतंकियों के पनाहगार थे। सरकार ने सभी छोटे-बड़े अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में लगे जवान और सरकारी सुविधाएं वापस ले लीं। 14 फरवरी को राज्य सरकार ने जब अलगावादियों को दी सरकारी सुविधाएं वापस लीं तो देश ने एक स्वर में इसे सराहा, इसे बहुत पहले किये जाने की जरुरत बताई। खैर, देर - सबेर ही सही, यह निर्णय आतंकियों के पनाहगार के हौसलों को पस्त करने वाला था। घाटी में आतंकी विचारों को पनाह देने वाले संगठन जमात - ए - इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

केवल सरकार ही नही, आम नागरिक और कई संगठन भी पाकिस्तान को इस हमले के बाद अपने तरीकों से सबक सिखाने में जुटे थे। पूरे विश्व में भारतीय नागरिकों ने पाकिस्तान के दूतावासों के आगे प्रदर्शन किये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने आतंकी हमले के खिलाफ़ प्रस्ताव पारित किया। डीस्पोर्ट ने पाकिस्तान प्रीमियर लीग से अपने हाथ खींचकर इसके भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी। आतंक प्रभावित पाकिस्तान में जिस क्रिकेट से उसकी आय होती है, उस आय के स्रोत पर यह बड़ा प्रहार था। देश के कई हिस्सों में अन्तर - राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से पाकिस्तानी खिलाड़ियों, विशेषकर पूर्व कप्तान और वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर हटा दी गयी। इधर भारतीय सेना ने भी 14 फरवरी के वीभत्स हमले के षड़यंत्र में शामिल 4 आतंकियों को 18 फरवरी के अपने स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया। इस ऑपरेशन में मारा गया एक आतंकी पाकिस्तान का था। जाहिर है पूरे विश्व में यह सन्देश गया कि बल्कि पाकिस्तान अपनी धरती से भारत में आतंक फैला रहा है।

वहीं दूसरी ओर, जब देश कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने में व्यस्त था, देश की सेना भी तैयारी में जुटी थी। सरकार से मिली खुली छूट और अपने पराक्रम के बल पर सेना ने जबाब देने की तैयारी की। ठोस सबूतों और इंटेलिजेंस के आधार पर हमले के ठीक तेरहवें दिन 26 फरवरी को भारतीय वायु

अभिनंदन का अभाविप ने किया अभिनंदन, बताया नये भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति से हुआ यह संभव

26 फरवरी को बालाकोट में आतंकवादियों के शिविरों को भारतीय वायु सेना द्वारा ध्वस्त किये जाने के बाद बौखलाये पाकिस्तान के द्वारा भारत के सैन्य ठिकानो को निशाना बनाने की कोशिश की गई लेकिन भारतीय सेना ने न केवल उसकी कोशिश को नाकाम किया बल्कि उसके अति आधुनिक एफ – 16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस क्रम में भारत का भी एक विमान क्रैश हो गया और वायुसेना के जाबांज विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे, जहां से पाकिस्तानी सेना के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन भारत की बेहतर कूटनीति और अंतर-राष्ट्रीय दबाव के बाद महज 60 घंटे के भीतर अभिनंदन को वापस करना पड़ा।

विंग कमांडर की स्वदेश वापसी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारत के वीर सपूत अभिनंदन के भारतभूमि पर सुरक्षित आगमन पर हार्दिक अभिनंदन किया है। विज्ञप्ति में परिषद् ने इसके लिए भारत सरकार और भारतीय सेना के सशक्त नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त की गई है। अभाविप की मानें तो भारत सरकार ने बेहतरीन कूटनीति का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर दबाव बनाने में सफल रही जिसके कारण अभिनंदन की वापसी तुंरत संभव हो पाया।

अभिनंदन के अद्भूत पराक्रम और शौर्य के कारण पाकिस्तान के अधिक उन्नत लड़ाकू विमान एफ – 16 जिस तरह नेस्तानाबूद हो गया, वह समूचे राष्ट्र के लिए गौरवशाली एवं स्फूर्तिदायक है जिसने हरेक भारतवासियों के रगो में रोमांच युक्त उत्साह का संचार किया है। अभाविप विंग कमांडर अभिनंदन के पराक्रम के लिए उनको सलाम करती है। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री ने अपने जारी वक्तव्य में कहा कि भारत माता के वीर सपूत अभिनंदन का अविस्मरणीय पराक्रम नये भारत की तस्वीर समूचे विश्व के समक्ष रखता है। अभिनंदन की वापसी ने यह संदेश दिया है कि भारत का नेतृत्व विश्व को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाली छवि के अतिरिक्त स्मार्ट, स्वयं की सुरक्षा में सक्षम तथा आतंकवाद के खिलाफ कठोर हुआ है।

पुलवामा हमले के विरोध में अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन

14 फरवरी को जम्मू – कश्मीर में हुए आत्मघाती हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 49 जवान शहीद तथा 35 गंभीर रूप से घायल हो गये। इस घटना के बाद देश भर में शोक एवं आक्रोश की लहर दौड़ गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा दिल्ली, मुंबई, भोपाल, वाराणसी, शिमला, पटना, रांची, इम्फाल, गुवाहाटी, बैंगलुरू, जम्मू सहित देश भर के सभी इकाइयों ने अलग – अलग शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक जगहों पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के कदम का अभाविप स्वागत करती है तथा सरकार से यह मांग करती है कि जब तक पाकिस्तान नापाक हरकतों को पूर्णतया बंद न कर दे तब तक पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का सहयोग न किया जाए।

अभाविप जम्मू – कश्मीर प्रांत के द्वारा राज्य के अलग – अलग स्थानों पर पुलवामा हमले के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया। जम्मू महानगर में परेड चौक से सिटी चौक तक आतंकवाद की शवयात्रा निकाली गयी एवं जम्मू के शालामर अस्पताल में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें अनेकों छात्रों ने रक्तदान किया। ऊधमपुर जिले में कार्यकर्ताओं ने 15 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला तथा 16 फरवरी को ऊधमपुर स्थित महाविद्यालय को बंद करवाकर आठ किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं लखनऊ में पुलवामा हमले के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जबकि छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजिल सभा का आयोजन किया गया।

त्रिपुरा में परिषद् के कार्यकर्ता पुलवामा हमले के बाद सड़क पर उतर आये। अगरतला में कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तर त्रिपुरा के कंचनपुर में तिरंगा रैली निकाली गई और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। केरल के अर्नाकुलम एवं त्रिवेन्द्रम में अभाविप के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे जलाये। चेन्नई में कार्यकर्ताओं ने प्रसिद्ध प्रेसीडेंसी कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। मुंबई में भी पुलवामा हमले के खिलाफ कार्यकर्ताओं में आक्रोश साफ दिखा। वर्ली, दक्षिण मुंबई आदि जगहों पर विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली एवं पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किये। महाकौशल प्रांत के सभी जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किये गये। उत्तरांचल में भी हरिद्वार, टिहरी, बड़कोट, ऋषिकेश, देहरादून जैसे स्थानों पर कैंडल मार्च निकाले गये। जोधपुर में परिषद् के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, आक्रोश मार्च में वक्ताओं ने कहा पाकिस्तान एक नापाक देश है, जो सामने से वार करने की हिम्मत नहीं रखता। वो बुजदिल आतंकवादियों को भेज कर धोखे से हमला कर सैनिकों और निर्दोष नागरिकों की हत्या करता है।

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए आकाश शर्मा की रिपोर्ट)

सेना के विमान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बालाकोट में घुसकर चंद मिनटों में ही जैश के आतंकी प्रशिक्षण के ठिकाने को तबाह कर सुरक्षित भारत वापस लौट आये। सक्षम और प्रभावी तरीके से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए मशहूर मिराज - 2000 विमानों ने पाकिस्तानी सीमा के अन्दर घुसकर जो कार्रवाई की, उससे पाकिस्तान के होश उड़ गए। अपनी सीमा के अन्दर हुए इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने जहां इस घटना को लेकर अपनी आपत्ति जताई, वहीं भारत ने पूरी दुनिया के सामने आकर साफ़ - साफ़ शब्दों में कहा कि यह हमला मानवीय अथवा सैनिक प्रतिष्ठानों पर नही, आतंकी ठिकानों पर था। देश की सुरक्षा के लिए हम ऐसे कदम और उठाते रहेंगे। 1971 के युद्ध को छोड़ दें, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में भारत की जांबाज सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था, तो पाकिस्तान के अन्दर में घुसकर वायु सेना द्वारा की गयी यह कार्रवाई पहली घटना थी। जबाबी कार्रवाई में अगले दिन पाकिस्तान की वायु सेना ने जब भारतीय

क्षेत्र में घुसकर सैनिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पहले से अलर्ट सेना ने न केवल उन्हें वापस लौटने को मजबूर किया बल्कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन लड़ाकू फाइटर विमान F-16 को भी मार गिराया। अफ़सोस 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायु सेना की हरकत का जबाब देने के क्रम में मिग - 21 विमान क्रेश हो गया और इसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन गिरे। भारत की कूटनीतिक पहल और अन्तराष्ट्रीय दबाब के आगे झुकते हुए पाकिस्तान 60 घंटों के अन्दर ही विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाने पर मजबूर हो गया।

एक तरफ जहां सेना हमले के जिम्मेवार आंतकियों के सफाए में जुटी थी, देश की सरकार आतंरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने पाक - परस्त अलगाववादियों पर लगाम कसने में जुटी थी, कूटनीतिक स्तर पर भारतीय विदेश मंत्रालय और दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावास पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बारे में अवगत कराकर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर उसे अलग-थलग करने की कोशिशों में जुटे थे, वहीं पुलवामा हमले के बाद देश के अंदर हुई कुछ गतिविधियां बेहद चिंताजनक थी। देशभर में जब वीर जवानों को खोने का दर्द ताज़ा ही था, उनके परिवार के प्रति देश भर में लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, हमले के जिम्मेवार रहे लोगों को दण्डित करने की मांग कर रहे थे तब दूसरी ओर देश - विरोधी विचारों के लोग सोशल मीडिया के जरिये न केवल शहीदों के अपमान में जुटे थे बल्कि देश के साथ खड़ा होने की वजाए ऊलजुलूल तर्कों से सरकार को घेरने और अपशब्द लिखने में व्यस्त थे। सोशल मीडिया पर जब राष्ट्रवादी ताकतों ने विरोध किया तो पुलवामा के हमले से उद्वेलित राष्ट्रीय भावना को एक अलग तरह की दिशा देने की नाकाम कोशिश हुई। चुनाव जीतने के लिए ये हमला मोदी ने करवाया - ऐसे तर्कों को हवा देने में न केवल पाकिस्तानी मीडिया जुटी हुई थी बल्कि इसमें मोदी विरोध में देश विरोध पर उतारू भारत के अन्दर के कुछ छद्म बौद्धिक भी शामिल थे। जब सरकार ने सेना को छूट दी और भारतीय वायु सेना ने एयरस्ट्राइक किया तो न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत में पाक-प्रेमियों ने भी सबूत मांगने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब 27 फरवरी को विपक्ष के 21 दलों ने प्रस्ताव पारित करके सरकार पर सेना की शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी हों दिग्विजय सिंह, विपक्ष के कई नेताओं और पाक-परस्त बुद्धिजीवियों ने सरकार और सेना की बातों पर भरोसा करने की बजाए एयरस्ट्राइक के परिणाम को लेकर सवाल उठाये। ध्यान रहे इनमें से अधिकांश दलों ने 2016 में उरी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे।

पुलवामा हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया से न केवल कई मिथक टूटे बल्कि एक नया इतिहास भी बना है। बार-बार हमले झेलकर भी अमूमन शांति-सन्देश का राग अलापने वाला भारत इस बार पूरी दुनिया में यह सन्देश देने में कामयाब रहा कि अगर आतंक के पोषक देश भारत के विरुद्ध साजिश रचेंगे तो वे अब बर्दाश्त नही किये जायेंगे। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने एक अलग लकीर खींची और सदैव इस बात को दुहराया कि हम किसी देश के खिलाफ़ नही है, हम आतंक के खिलाफ़ है और हमारी लड़ाई अब केवल रक्षात्मक नही होगी। हम आगे बढ़कर आतंक को जड़ से समाप्त करने का माद्दा भी रखते है। नए भारत की इस छवि से परेशान पाकिस्तान की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में तुर्की को छोड़कर उसके साथ कोई खड़ा नही था। यहाँ तक कि विश्वस्त साथी चीन ने भी खुलकर साथ देने से हाथ खड़े कर दिए।

पुलवामा हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया से न केवल कई मिथक टूटे बल्कि एक नया इतिहास भी बना है। बार-बार हमले झेलकर भी अमूमन शांति-सन्देश का राग अलापने वाला भारत इस बार पूरी दुनिया में यह सन्देश देने में कामयाब रहा कि अगर आतंक के पोषक देश के विरुद्ध साजिश रचेंगे तो वे अब बर्दाश्त नही किये जायेंगे। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने एक अलग लकीर खींची और सदैव इस बात को दुहराया कि हम किसी देश के खिलाफ़ नही है, हम आतंक के खिलाफ़ है और हमारी लड़ाई अब केवल रक्षात्मक नही होगी।

ऐसे समय में जब देश आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान को सबक सिखाने और उसे अपनी धरती से आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए विवश करने में जुटा है, देश के उन लोगों से हमें सावधान रहने की जरुरत है जो खाते है हिंदुस्तान का और गाते है पाकिस्तान का। कश्मीर में आतंक के पोषक तत्वों के जड़ से खात्में के लिए केवल सेना नही, देश के आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं को भी जागरूक और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। ■

शिक्षा ऐसी हो जो मानवता की रक्षा करे : डॉ. एस. सुबैय्या

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए तमिलनाडु प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कर्णावती में आयोजित अभाविप के 64 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित डॉ. एस. सुबैय्या मूलतः तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले से हैं। डॉ. सुबैय्या चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि डॉ. सुबैय्या के अब तक एक हजार से अधिक सर्जरी, 27 चिकित्सीय शोधपत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र – पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ. एस. सुबैय्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अभाविप के कार्य समेत तमाम समसामयिकी विषयों को लेकर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के सहायक संपादक अजीत कुमार सिंह ने डॉ. सुबैय्या से बात की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश –

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा ?

बात 1986 की है जब मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद् से जुड़ा, तब से लेकर आज तक मैं कार्यकर्ता के रूप में परिषद् में कार्य कर रहा हूं। परिषद् में कार्य करते - करते उम्र के साथ – साथ मानसिक रूप से बढ़ा हूं। अगर मैं परिषद् से नहीं जुड़ता तो संभवतः उम्र के साथ मानसिक और वैचारिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता। जैसे – जैसे मेरा अनुभव बढता गया, परिषद् के द्वारा अलग – अलग दायित्व दिया जाने लगा। परिषद् के द्वारा मुझे जो भी दायित्व दिया गया मैंने उसे ईमानदारीपूर्वक निभाने की कोशिश की। परिषद् में कोई पद नहीं होता, यहां पर दायित्व होता है और सभी लोग कार्यकर्ता भाव से अपने - अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। परिषद् के माध्यम से मैंने भारतीय समाज के वास्तविक हालात को जाना। आज भी मैं परिषद् के कार्यों और प्रवास के माध्यम से कुछ – न – कुछ सीख रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व में आने के बाद प्रवास बढ़ा है, पहले की अपेक्षा देश भर में जाने का मौका ज्यादा मिल रहा है। अगर सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर के बारे में आप पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब होगा कि कल भी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं।

भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति एवं उसमें सुधार के उपाय बताएं।

भारत की शिक्षा पद्धति रोजगार के लिए नहीं वरन मानसिक विकास के लिए होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो मानवता की रक्षा करे एवं छात्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करे। सरकार को भारत एवं भारतीयता को केन्द्र में रखकर शिक्षा पद्धति बनानी चाहिए। मुझे लगता है हमारी प्रारंभिक शिक्षा मूल्य आधारित होना चाहिए जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करे, उसे चरित्रवान बनाये एवं उसके अंदर स्वावलंबन का भाव विकसित करे। रोजगार के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसकी

रूचि के अनुसार उसे उस क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षा टू-वे ट्रैफिक के अनुसार होना चाहिए न कि आज की तरह वन-वे ट्रैफिक जैसा। मुझे पता है इसे लागू करने में कठिनाई होगी लेकिन इसका दूरगामी परिणाम सुखद होगा।

एक चिकित्सक होने के नाते आप भारत की चिकित्सा प्रणाली को किस प्रकार से देखते हैं ?

चिकित्सा क्षेत्र में दिनोंदिन सुधार हो रहा है, मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा है। विदेश के लोग भी भारतीय चिकित्सा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पिछले चार सालों में सरकार ने भी चिकित्सा के क्षेत्र में काफी काम किये हैं। भारत की चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो यह उल्टे पिरामिड की तरह है। वर्तमान समय में मेडिकल शिक्षा प्रणाली में अनेकों कमियां हैं। जब तक चिकित्सा क्षेत्र में सुधार नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पायेगी। जमीनी स्तर पर आज भी चिकित्सा शिक्षा आम छात्र के पहुंच से काफी दूर है। हमें चिकित्सा शिक्षा को प्राथमिक स्तर से लागू करना चाहिए ताकि आम छात्र अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। अभाविप के प्रकल्प मेडिविजन के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। हम इसमें सफल भी हुए हैं लेकिन अभी बहुत से कार्य किये जाने बाकी है।

अभाविप की आगामी योजनाओं के बारे में बताएं।

विद्यार्थी परिषद् 365 दिन काम करने वाला छात्र संगठन है। परिषद् का कार्य क्षेत्र बढ़ा है, आज हरेक क्षेत्र में परिषद् के आयाम हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिविजन, कृषि के क्षेत्र में एग्रीविजन, तकनीक एवं प्रीमियर संस्थानों में थिंक इंडिया, कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय कला मंच, पर्यावरण व विकास के क्षेत्र में विकासार्थ विद्यार्थी (एस.एफ.डी.), फार्मासिस्ट छात्रों के लिए फार्माविजन, आयुर्वेद क्षेत्र में जिज्ञासा जैसे आयाम कार्य रहे हैं। गत वर्ष हमने 'सेल्फी विद कैंपस' अभियान के माध्यम से देश भर के चालीस हजार से अधिक महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में पहुंचने का काम किया, मिशन साहसी अभियान के तहत लगभग सात लाख छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। इस वर्ष आम चुनाव होने हैं इस निमित्त हम देश भर में मतदाता जागरण अभियान चलाने वाले हैं साथ ही पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिशन साहसी, सामाजिक अनुभूति, छात्रावास संपर्क अभियान चलाये जाने हैं। ■

सम्मेलन

गौरवशाली परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति : चौहान

देश के उज्ज्वल भविष्य और समाज को सही दिशा देने में युवाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। गौरवशाली परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी ताकत के बलपर भारत आज विश्वपटल पर सबसे ताकतवर देश उभर रहा है। अंतरिक्ष, व्यापार, विदेश नीति, शाश्वत विकास, रक्षा, सड़क निर्माण जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने एक ऊंची उड़ान ली है। इस ताकत को हमें और आगे बढ़ाते हुए बरकरार रखना है। ये बातें अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने संभाजीनगर में आयोजित 'संकल्प युवा नेतृत्वाचा' सम्मेलन में कहीं।

वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागड़े (नाना) ने कहा कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मन केवल अभाविप के संस्कारों में ही बन सकता है। अभाविप राष्ट्रभक्त छात्रों का निर्माण करती है और वही छात्र इस देश को विकास पथ पर आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। अभाविप, महाराष्ट्र प्रांत के प्रदेश मंत्री स्वप्निल बेगड़े ने कहा कि अभाविप का इतिहास समाज और छात्रों को सही दिशा में जाने के लिए पथदर्शक है। एकदिवसीय छात्र सम्मेलन का समापन करते हुए अभाविप के पश्चिम क्षेत्र संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में युवा नेतृत्व आगे लाने का काम अभाविप अपने स्थापना काल से ही कर रही है। सम्मेलन में मराठवाड़ा के आठ (8) जिला क्षेत्र एवं 62 तहसील क्षेत्र से 2517 छात्रों ने सहभाग लिया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. सुरेश मुंढे , प्रदेश संगठन मंत्री श्री रायसिंह , प्रदेश सहसंगठनमंत्री अभिजीत पाटिल , प्रदेश सहमंत्री कु.अंकिता कामठीकर उपस्थित थे। ■

National Security and Rafael Deal

DR. SWADESH SINGH

The recent escalation with Pakistan and the government's bold decision to take the fight to the enemy territory has brought Indian's national security and air power into sharp light. Speaking at a media event recently, Prime Minister Narendra Modi said that the air strike on Pakistan would have been even more deadly if India had Rafael fighter aircraft.

The Rafael fighters had been in news for months preceding this. Within a matter of two years, the BJP government had finalised the deal to procure the Rafael jets throwing into sharp contrast the dilly-dallying by the previous governments on the matter. With the general election in the offing, the Congress turned to the game of misdirection and raised questions on Rafael deal.

The deal reached by the BJP-led Central government ensures that the country will get weaponised fighter jets in fly-away condition. The deal includes latest weapons like the Meteor and Scalp missiles, besides a five-year support package. This is far ahead of the deal that the former Congress-led governments had been drafting and which entailed only the jets without any weaponry.

The need for these weapons was felt in the aftermath of the Kargil War. The BJP-led government then had given a nod for procurement of these aircraft. But the government did not return after the elections and what followed thereafter is a tale of criminal delay and vested interests undermining the security of the nation. The Congress-led government that stayed in power from 2004 to 2014 could not finalise the deal in 10 years. The Indian Air Force, during this period, continued to struggle with fatalities in the wake of old aircraft and frequent crashes. News of young pilots losing lives for nothing became common news. In 2007, the IAF framed its requirements and issued the tender but even then the government could not arrive at a deal with the French manufacturer Dassault Aviation.

This sequence of events begs the crucial question that why was the then government not able to reach a deal from 2007 to 2014? The deal now finalised is a government-to-government deal which does not involve any middlemen or agents, thus eliminating any scope of corruption or malpractices. However, with the Congress government constantly attempting to delay and thwart the deal, the security of the country has come under threat.

In the wake of the delays and misinformation created by the Congress, the Chief of Indian Air Force Marshal BS

Dhanoa also asserted that the current deal is a good one. He clearly stated that there was "no overpricing" in the Rafale purchase as the government had "negotiated a very good" deal for the French fighter aircraft.

To put things in context of India's defence security needs we also need to look at the capabilities of the Rafael aircraft. It is a double-engine medium multi-role combat aircraft. The manufacturing company claims that the aircraft can perform several actions at the same time, such as firing air-to-air missiles at a very low altitude, air-to-ground, and interceptions during the same sortie. It can also, reportedly, carry out a wide range of missions encompassing air defence or superiority, reconnaissance, close air support dynamic targeting, air-to-ground precision strike or interdiction, anti-ship attacks, nuclear deterrence, refuelling, etc. Importantly, India has been able to negotiate the acquisition of latest weapons package for Rafael.

Along with the aircraft the deal provides for Scalp (a precision long range ground attack missile that has a range of 300 km, capped by the missile technology control regime) as well as Meteor (a beyond visual range air to air missile that can take out enemy aircraft at range of over 100 km). Besides this, the deal also caters to some specific needs of the Indian Air Force. These include, helmet mounted sights and targeting system, ability to taken off from high altitude airbases like Leh, a radar warning receiver, a towed decoy system to thwart incoming missile attacks and French industrial support for fighter for 50 years.

Since the turn of the century, Indian military planners have struggled with the challenge to replace the fleet of MiG-21, MiG-23 and MiG-27 fighters that have been steadily retired from service. In the present state of Indian air fleet, the Air Force needs multi-role combat aircraft that could also be used as airborne strategic delivery systems, and Indian air defence experts have found Rafael to fit the bill. Experts say these planes will give India a modestly more effective strike force than the aging one it has now. India's requirement is also acute in the context of growing air power with both China and Pakistan. The two neighbouring countries have consistently maintained far more well-equipped air defence fleets than that of India. Beijing is also reportedly selling Islamabad its sophisticated fighter aircraft, warships and ground systems, building up Pakistan as its tacit extension in South Asia. The capability gap between Indian and Chinese armed forces continues to grow in the wake of snail paced procurements by India.

In conclusion we can say that Rafael deal is good deal which was delayed by the previous Congress government and the current government led by Prime Minister Narendra Modi has done a fair deal. In coming months we will see Rafael flying in Indian skyline.

Before Prime Minister Narendra Modi's bold step to silence terrorism at its root, even Pakistan had been flying high on military and Air Force reinforcements and upgradations and claiming that it could look India in the eye. Infact, even during the recent skirmish with India, Pakistan reportedly used the advance F16 jets it had acquired from the United States of America. Though the fact that it was downed by India's archaic MiG 23 piloted by the now legendary Squadron leader Abhinandan Varthaman, left even the defence experts baffled.

In conclusion we can say that Rafael deal is good deal which was delayed by the previous Congress government and the current government led by Prime Minister Narendra Modi has done a fair deal. In coming months we will see Rafael flying in Indian skyline. ■

(Author teaches Political Science in Delhi University)

कृषि शिक्षा उत्थान पर है सरकार का विशेष जोर : राधामोहन सिंह

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रकल्प एग्रीविजन कार्यशाला में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने कृषि शिक्षा के उन्नयन पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा के उत्थान के लिए विश्व बैंक तथा भारत सरकार के सहयोग से 11 सौ करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना की शुरूआत की गई है। कृषि मंत्री ने देश के कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में किये गये संशोधनों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने पांचवीं डीन कमेटी का गठन किया था, जिसकी सिफारिशें अब सभी कृषि विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गई है।

वहीं अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने देश की कृषि तथा कृषि शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने हेतु विद्यार्थी परिषद् द्वारा किये जा रहे सकारात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज से चार वर्ष पूर्व विद्यार्थी परिषद् द्वारा शुरू किये गये प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज देश की कृषि शिक्षा तथा किसानों को केन्द्र में रखकर सरकार को अपनी नीतियां बनानी पड़ रही है। इस प्रयास के लिए मैं परिषद् के एग्रीविजन आयाम को बधाई देता हूं। राष्ट्रीय सह – संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कृषि विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवाओं को कृषि क्षेत्र की समस्या के समाधान का हल ढूंढना होगा तभी हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं। कार्यक्रम के आयोजन सचिव डा. रघुराज किशोर तिवारी ने एग्रीविजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। एग्रीविजन के राष्ट्रीय प्रमुख सुरज भारद्वाज ने बताया कि सम्मेलन में 66 कृषि विश्वविद्यालयों , 9 निजी कृषि संस्थानों तथा छह राष्ट्रीय कृषि संस्थानों से कुल 1163 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 234 छात्राएं शामिल हैं। राष्ट्रीय संयोजक गजेन्द्र सिंह तोमर ने एग्रीविजन के द्वारा की जा रही वर्ष भर की गतिविधियों से सभी को परिचित करवाया। इस मौके पर देश भर में पढ़ रहे कृषि छात्रों की समस्याओं व सुझावों पर एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। सम्मेलन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, उपमहानिदेशक डॉ. एन. एस. राठौर, निदेशक डा. ए. के. सिंह, अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यशाला के उपरांत एग्रीविजन 2019 के राष्ट्रीय सलाहकार समिति की घोषणा की गई। ■

रिपोर्ट – प्रियंका गिलहरी

कुम्भ की शिक्षाओं को संजोए रखें युवा

| रामाशीष यादव |

प्रयागराज का दिव्य कुम्भ - भव्य कुम्भ बीत गया। और दे गया दुनिया को कल्याण के अनगिनत मार्ग। समझा गया - आनन्द व सुख के बीच का अंतर। एक छोटे से जनपद में संपूर्ण भारत का दर्शन करा गया। ऐसे ही यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक विरासत नहीं है। यह जितना प्राचीन है, उतने ही नवीन शिक्षाओं को धारण किये हुए है। इसकी शिक्षाएं नैसर्गिक हैं। जब तक धरती रहेगी, कुम्भ का संदेश मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता रहेगा। कुम्भ हमारे पूर्वजों की धरोहर है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसको सौंपकर पूर्वज चले गये। इसकी शिक्षाओं को संजोए रखना हमारी (युवाओं) जिम्मेदारी है। कुम्भ धार्मिक व आध्यात्म का संगम तो है ही, साथ ही लाखों वर्षों की भारत की ज्ञान-विज्ञान की परंपरा, समावेशी व्यवहार, विविधता में एकता और वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को फलीभूत करने का सशक्त माध्यम भी है। यहां ज्ञान, तर्क, विज्ञान, धर्म व आध्यात्म एवं समाज के विषयों पर मंथन होता है। यह मंथन ऋषियों - मुनियों, साधु - संन्यासियों, समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्ग, बुद्धिजीवियों और ज्ञान-पिपासुओं के द्वारा होता है। इस संगम में चिंतन और मंथन से मानव के लिए उपयोगी विचार, नीति, सिद्धांत व मार्गदर्शी व्याख्याएं निकल कर आती हैं। यहां साधु-संतों के मुखारविंद से जीवन को सुचारू रूप से चलाने के सूत्र मिलेंगे। पूरी धरती को ही किस प्रकार स्वर्ग बना दिया जाए, इसपर यहां चर्चा होती है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली तरंगें यहां दिखाई देती हैं। इन्हीं शिक्षाओं के कारण कुम्भ अपनी छटा विश्व भर में बिखेर रहा है। दुनिया भारत की ओर नजरें टिकाए हुए है। क्या इन्हीं शिक्षाओं की खोज में हैं आप भी? अगर हां तो कुम्भ आते रहिए, चाहे जहां रहिये। यहां आने के लिए न कोई निमंत्रण, न ही कोई आह्वान होता है। फिर भी यहां देश-दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। यहां कल्पवास करने के लिए साधु, संत, महात्मा और गृहस्थ सभी आते हैं। विधि विधान से अपनी दिनचर्या नियम व अनुशासनों का पालन करते हुए सात्विक दिन व्यतीत करते हैं। यहां जाति, क्षेत्र, रंग, मजहब आदि किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। आपको भ्रम है कि अमुक जाति, मजहब, क्षेत्र आदि के व्यक्तियों के प्रवेश पर निषेध है तो

उन विकारों को मन-मस्तिष्क से निकाल फेंकिए। बिना भेदभाव के अमीर-गरीब हर कोई यहां संगम में डूबकी लगाकर स्वयं को धन्य व आनंदित महसूस करता है। सामाजिक समरसता का ऐसा विशाल पर्व दुनिया में और कहीं फिलहाल तो नहीं है। हिन्दुओं का यह कुम्भ पर्व विदेशियों को भी खींच लाता है। वे आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना बड़ा आयोजन अपने आप कैसे अनुशासित रहता है। यह कुम्भ भविष्य के सुनहले स्वप्न बुनते समय धर्म और आस्था को केन्द्र में रखने का संदेश देता है। सनातन संस्कृति की कुम्भ परम्परा को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यूनेस्को द्वारा इस उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिया जाना प्रत्येक भारतीय व हिन्दुओं के लिए गौरव का विषय है। यह साधारण निर्णय नहीं है। 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया में यह हमारे प्राचीन भारत व ऋषियों के जीवन मूल्यों की स्थापना है। दुनिया ने भारत का पहले भी लोहा माना है, अब भी मान रही है और आगे भी लोहा मानेगी। क्योंकि हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज व परंपराएं ढकोसला नहीं, अपितु पूर्णरूपेण वैज्ञानिक कसौटी पर खरे हैं। बाह्य कारकों के कारण कुछ विसंगतियां साथ चलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनमानस ने अपने वैज्ञानिक मानक के आधार उन्हें सहर्ष त्याग दिया। सनातन परंपरा में तुलसी पूजन हो या वट वृक्ष का पूजन यह सभी वैज्ञानिक मान्यता है। यह प्रकृति संरक्षण का व्रत है। सृष्टि रचना से लगाकर आज तक वैज्ञानिकों ने जितना भी खोज किया, उनकी वह खोज सदा से वेदों के अनुरुप ही रही है।

ऋषियों की नगरी प्रयागराज में होने वाला कुम्भ-2019 का ऐतिहासिक रहा। इसकी ऐतिहासिकता, भव्यता व स्वच्छता की चर्चा देश-दुनिया में हो रही है। इसबार कुम्भ मेला के अवसर पर तमाम गणमान्यों के बीच संगम में डुबकी लगाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आए। यहां आकर उन्होंने जो संदेश दिया, उसका परिणाम भविष्य में अवश्य देखने को मिलेगा। मेला में दिनरात साफ-सफाई के काम में जुटे पांच सफाईकर्मियों के पांव पीतल की थाली में उन्होंने अपने हाथों से पखारे। अंगवस्त्र देकर सम्मानित किए। यह साधारण सोच नहीं है। 'मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे' का अद्भूत उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी का यह कृतित्व भी इतिहास में दर्ज हो गया है। उन्होंने प्रयाग की पुण्यभूमि से सामाजिक समरसता का वैश्विक संदेश दिया। सनातन भारतीय संस्कृति व परंपराओं को दलित-गरीब विरोधी का प्रमाण पत्र बांटने वालों को भी जवाब मिल ही गया होगा। प्रधानमंत्री ने साफ-साफ संदेश दे दिया है कि हमारी सनातन संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार, उत्सव आदि मात्र मानवकल्याण के लिए हैं। यह भी समझाने में सफल रहे कि कर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। संपूर्ण कुम्भ का अध्ययन किया जाए तो योगी सरकार ने कुम्भ के माध्यम से भारतीय संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान व आध्यात्म की गौरवमयी विरासत को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। तीर्थराज प्रयाग का कुम्भ विश्व स्तर का आकर्षण केन्द्र बन गया है। ■

(लेखक हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में कार्यरत हैं।)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का फरवरी - मार्च 2019 का संयुक्तांक अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

मन से नहीं धन से हैं गरीब,गर्व करे हम आदिवासी हैं : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू

झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज के लोगों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए बेटा -बेटी में अंतर किये बिना दोनों को सामान शिक्षा देने के लिए जागरूक करें। आदिवासी भूखे मर जाते हैं पर भीख नहीं मांगते। ईमानदारी से खेतीबारी, मजदूरी करते हैं लेकिन दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते। आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं। आदिवासी सरल और निष्कलंक हैं और जरूरत पड़े तो भगवान बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत, सिद्धो-कान्हू जैसे वीर सपूत एवं अपनी धरती के लिए जान देने वाले भी हैं। खुद को ऐसा बनायें कि लोग आपकी मिसाल दें। उन्होंने कहा कि आदिवासी होने पर चिंता नहीं गर्व करें। आज यदि आदिवासी समाज के लड़के - लड़कियों से उसका नाम पूछा जाता है तो वे नाम के साथ अपना टाइटल कुमार व कुमारी बताते हैं। यदि आप आदिवासी हैं तो अपने नाम के साथ मुंडा, उरांव जो भी टाइटल हो,उसे बताइए। वे गुमला (झारखंड) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित जनजातीय छात्र जुटान को संबोधित कर रही थीं।

जनजातियों के उत्कर्ष में अभाविप की भूमिका अहम : साय

अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय जी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के उत्कर्ष और उन्नयन में विद्यार्थी परिषद काफी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय जीवन का अपना अलग महत्व है। परंतु कई जगहों पर जनजातीय समुदाय मुस्लिम हो गये हैं। जिस प्रकार से हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है उसी प्रकार जनजातीय समुदाय भी अनेक विविधताओं से भरा है। आने वाले समय में जनजातीय समुदाय ही देश का नवनिर्माण करेगा। इसके लिए जनजातीय समुदाय को जागरूक होना होगा, खुद को संगठित और मजबूत बनाना होगा।

साथ चलने से ही भारत बनेगा विश्वगुरू : रघुनंदन

अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के.एन रघुनंदन ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत व परम्पराओं को कैसे बचाना एवं संजोए रखना है, यह देश को जनजातीय समाज से सीखना चाहिए। जनजातीय समाज प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। जनजातीय क्षेत्र में अभाविप द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। कार्यक्रम में छात्रों से अधिक संख्या छात्राओं की है. जो इस बात का सबूत है कि आने वाला समय महिलाओं का होगा। आने वाले समय में पार्लियामेंट में 70 प्रतिशत महिलायें होंगी और देश को विकास की ऊंचाईयों तक ले जायेंगी। उन्होंने कहा कि अभाविप और जनजातीय समुदाय में कई समानतायें हैं। दोनों को अपनी धरती से प्यार है। देश

के जनजातीय समाज के विकास के बिना भारत की विकास गाथा अधूरी है।

जनजातीय समाज भारत का मेरूदंड है : आकांत

अभाविप के राष्ट्रीय सह – संगठन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान के भंडार वाले भारत, जिसमें नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। आज उस भारत को लाचार, गरीब व दरिद्र आदि की संज्ञा दी जाती है जो वास्तविकता से परे है। भारत के युवाओं को अपने सामर्थ्य को समझ कर देश को विकास के पथ पर लाने की आवश्यकता है। जनजातीय समाज भारत का मेरूदंड है। आजादी की लड़ाई तथा अंग्रेजों की हुकूमत के समय जनजातीय समाज का योगदान अनुकरणीय है। इसी कारण अंग्रेजों द्वारा जनजातीय समाज को पिछड़ा, गरीब व निकृष्टों की संज्ञा दी गयी फिर भी भारत से जनजातीय संस्कृति को वे तोड़ नहीं पाये।

जनजातियों की भाषा और संस्कृति को सीखने के लिए लोग ललायीत हैं : पद्मश्री अशोक भगत

विकास भारती बिशुनपुर के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि जनजातीय समुदाय को समाज और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम अब हो रहा है। जनजातीय समुदाय की भाषा, कला, परंपरा, संस्कृति सारी दुनिया से अच्छी है। इसे दूसरे लोग भी सीखने को लालायित हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इतिहास में इसे छुपाकर रखा गया। हमारे सीधेपन और भोलेपन के कारण लोग दबाते रहे हैं लेकिन अब दबना नहीं है। नये जमाने में नयी चुनौतियां हैं फिर भी आगे बढ़ना है।

जुटान कार्यक्रम जनजातीय छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा : दिनेश उरांव

जुटान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा अभाविप द्वारा आयोजित यह सम्मेलन आने वाले दिनों में छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विद्यार्थी परिषद् ऐसा संगठन है जो स्वस्थ और समावेशी समाज के निर्माण की बात करती है। यह केवल छात्र संगठन नहीं बल्कि सामाजिक संगठन है जो देश में हो रहे सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखती है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सहयोग करती है।

जनजातियों ने अपने स्वाभिमान व संस्कृति को धरोहर की तरह संभाल रखा है : नाथू गाड़ी

अभाविप के प्रांत अध्यक्ष नाथू गाड़ी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपने स्वाभिमान और संस्कृति को धरोहर के रूप में संभालकर रखा है। परंतु देखा जा रहा है कि कहीं-कहीं पश्चिमीकरण हावी होता जा रहा है । लोग अपनी परंपरा व सभ्यता को भुलाते जा रहे हैं। विभिन्न तरह से जनजातीय समुदाय पर हमला हो रहा है। वे ठगे जा रहे हैं । हमें अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखना है।

कॉपरेटिव बैंक रायडीह के प्रबंधक सह जेएफए के उपाध्यक्ष सागर उरांव ने कहा कि अभाविप राष्ट्रीय विचारधारा के संवाहक के रूप में काम कर रही है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में इनकी भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म से भी ऊपर उठकर कुछ है तो वह है मातृभूमि। अभाविप और जनजातीय समुदाय में मातृभूमि के प्रति समानता है। अभाविप अपनी मातृभूमि के लिए जान दे सकती है। उसी प्रकार जनजातीय समुदाय भी अपनी धरती के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं।

रांची की महापौर और अभाविप की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा कि संघर्ष की आग में जब सोना तपता है तो वह कुंदन बन जाता है। अभाविप के पुरातन कार्यकर्ता संघर्ष के बल पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा कर रहे हैं। संघर्ष से उपजे परिषद के कार्यकर्ता ही वर्तमान पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के रोल मॉडल हैं। प्रेरणा के स्त्रोत हैं। परिषद अपने कार्यकर्ताओं को मांजता है। विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है।

सम्मलेन को अभाविप के जनजातीय छात्र कार्य प्रमुख जे. राम. मोहन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, प्रांत संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, प्रांत मंत्री रोशन कुमार, मिशिर कुजूर ने भी संबोधित किया। इस दौरान झारखंड में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने, छात्रवृत्ति में वृद्धि एवं नेट व पीएचडी इंजनियरिंग द्वारा चयनित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान करने, प्राथमिक शिक्षा में मातृ एवं क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित करने, पूरे प्रदेश में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ जनजातीय छात्रावासों का निर्माण कराने और जड़ी-बूटियों की महत्ता समझते हुए उसका उपयोग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। दो दिवसीय जुटान कार्यक्रम में प्रदेश भर से दो हजार से अधिक जनजातीय छात्र – छात्राओं ने भाग लिया। ■

NRC : A Glance

DR.TUSHAAR KANTI

On the basis of the Geographical position and the peripheral boundaries, some north-eastern states have become very sensitive and demand serious note on the security and socio economic perspectives which has been affecting almost all sections of people actively or passively .Although, this highly sensitive issue had been persisting for a quite long time amidst the different government's rules and despite very sincere commitment also no plan was carried out by not a single Govt. But unlike other Govt. NDA had shown its keenness materializing the intensely awaited NRC updation programme under the prevailing guidelines and monitoring of the honorable Supreme court. The National Register of Citizens(NRC)is a register containing names of all genuine Indian citizens residing in Assam .The Register was first prepared after the 1951,census of India .Although NRC updation is a nationalized programme which should be considered as the top priority and need of the hour for the sake of the citizens of India .Considering the illegal Bangadeshi migrants or infiltrators who have crossed the border after the stipulated time and sheltered in any state of Assam ,Meghalaya or Tripura have grievously affected and damaged the socioeconomic perspective of the whole northeast besides directly concerning Assam and Tripura only because of unexpected easy access to India through the open, unmanned and unbound boundary issues.

The update process of NRC started in the year 2013 under the strict monitoring of Supreme Court of India .Needful to mention that NRC is a list of people who have been able to prove that they were in India before the midnight of march 24th 1971 exactly when neighboring Bangladesh declared independence.It's a list of genuine Indian citizen, determined by Laws unique to the state of Assam.

It is seen, witnessed that during the inception of the NR updating process , followed by the apex court's order ,some opposition parties ,illmotived political leaders of different communities desired to disrupt the long awaited process .Surprisingly some raised NRC issue in Assam assembly too stating many circustic excuses but had to keep mum eventually . NRC was prepared in 1951, after the Census of 1951.It is the register containing details of all Indians citizens .NRC updation basically means the process of enlisting the names of all citizens residing in Assam at all the time of NRC updation basically means the process of enlisting the names of all citizen residing in Assam at te time of NR updation.

The another prime purpose of updating NRC is an exercise to ensure that the genuine Indian Citizens are not deprived of the entry of their names in the Register and are assured about what they virtually deserve.

The acceptance of the entire stream of immigrants from the data of the Independence of the country till 24th March 1971 is not only a recognition of the historical situation of the birth of Bangladesh but for the Autochthons, it is a big Sacrifice of their interests and rights on their native soil. A database of all the citizens of Assam was prepared; citizens had to prove that they or their ancestors had been residents of the state before 24th March 1971.

This important point needs attention that, People who came from Bangladesh between January 1, 1966 to March 24, 1971, registered

themselves with the Foreigner Regional Registration Office and were declared by the Foreigner Tribunal as Indian Citizens. Now question might arise if an individual does not get himself could be a victim of Administrative or legal problems, May receive a notice from one of the 100 foreigner tribunals in Assam to establish his Indian citizenship may face deportation or jail as a stateless person.NRC forms the basis for the detection of illegal immigrants; inclusion in the NRC list will be a shield against harassment and a ticket to enjoy all the constitutional rights and safeguards. The issue of illegal Bangladesh migrants which has been the key reason of harming the development, peace and tranquility of Assam mainly out of other north-eastern states due to its economic ,ethnic and religious dimensions. Speedy resolution of NRC and Assam Accord is therefore in need of the hour. It must be allowed to reach its logical conclusion without giving it a communal or political color .The Supreme Court has finally set a deadline of July 31 for the release of the final National Register of Citizens (NRC) without fail and asked the Assam government and the EC to make sure that the highly significant exercise doesn't collide with the upcoming Lok sabha elections. "The NRC and elections must receive equal importance, proceed without affecting each other," a bench led by the CJI Ranjan Gogoi said on Thursday.

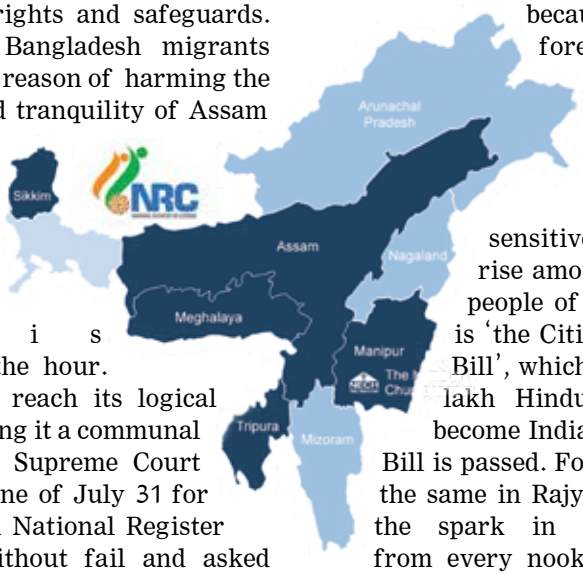

An estimated 30 lakh people have filed their claims until December 30 to be included in the National Register of Citizens (NRC), the final draft of which had left out over 40 lakh applicants due to lack of credible documents. Authorities have also received around 600 objections to the inclusion of names on the list, published on July 30. The draft NRC left out at least 40 lakh residents of the state. The apex court, which directed compilation of the NRC to weed out illegal migrants, had at the last hearing allowed those left out to submit fresh claims for inclusion by December 15. Very importantly, in the three Assam districts bordering Bangladesh, population had increased faster than the rest of India during 1981-1991. From the above, it can be assumed that the infiltration of foreigners from Bangladesh contributed significantly to the sharp increase of population in Assam for sure.NRC final draft has left a section of leaders in Assam's ruling BJP dissatisfied, because they say many foreigners have made it to the document that has left out a large number of genuine Indian citizens.

Another very sensitive issue has been on rise amongst the all sections of people of Assam and north east is 'the Citizenship (Amendment) Bill', which claims that around 20 lakh Hindu Bangladeshis would become Indians if the controversial Bill is passed. Following the pass out of the same in Rajyasabha has augmented the spark in it.Widespread protest from every nook and corner in terms of agitation, rally, and protest are the outburst of people o Assam and northeast on every day.

Although many political leaders left no stone unturned to politicize this very significant and historical issue but eventually the genuine and virtual citizens and residents of Assam,It is very disheartening that in the long ,repeated process some original citizens were left out in the due process of documentation yet kept patience to prove their inheritance .Tripura and other relevant states have thoroughly comprehended the significance of the same and now they themselves have come out wholeheartedly to embrace the constitutional right which every Indian deserve . ■

राष्ट्रीय कला मंच के मदारी महोत्सव में दिखी लोक कला की झलक

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रकल्प राष्ट्रीय कला मंच द्वारा जनवरी माह में दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में 'मदारी कला महोत्सव' का आयोजन किया गया । इस तीन दिवसीय मदारी महोत्सव में लोक कला की झलक देखने को मिली। मदारी महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कला मंच के संयोजक ध्रुव कांडपाल ने बताया कि यह मदारी का लगातार तीसरा संस्करण है। इस वर्ष लगभग सौ संस्थाओं ने पंजीयन कराया। महोत्सव को तीन भागों क्रमशः खिचड़ी, ग्राम्य और धरोहर में बांटा गया, जिसमें दो हजार से अधिक छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि पहली बार ललित कलाओं के लिए प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जिसमें दिल्ली के 20 संस्थानों ने भाग लिया।

मदारी महोत्सव का उद्घाटन अभाविप के राष्ट्रीय सह – संगठन मंत्री श्रीनिवास एवं बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। नवाजुद्दीन ने कहा दिल्ली से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं लंबे समय तक एनएसडी से जुड़ा रहा हूं। इस दौरान उन्होंने छात्रों को अभिनय के गुर भी सिखाए। अभाविप के राष्ट्रीय सह – संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि मदारी महोत्सव में विविध विषयों को पेंटिंग्स तथा स्ट्रीट प्ले के माध्यम से अभिव्यक्त कर समाज को आईना दिखाने का काम किया है, जिससे सीख लेकर छात्र समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं।

महोत्सव के पहले दिन लैंगिक समानता, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किये गये थे एवं आधुनिक कला, लोक कला, मधुबनी पेंटिग जैसे विभिन्न विषयों को समेटे हुए लगभग 12 प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। कुछ नाटक विश्वविद्यालय में फैल रहे अर्बन नक्सल, भारत की समाप्त होती संस्कृति, मतदाता जागरूकता जैसे विषयों को सीधे प्रभावित करने वाले थे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडली में पत्रकार अतुल गंगवार, लेखक नरेश शांडिल्य एवं प्रमोद शास्त्री थे।

प्रतियोगिता में इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स एवं राजधानी कॉलेज की टीम संयुक्त रूप से प्रथम स्थान, अरविंदो कॉलेज दूसरे स्थान एवं तीसरे स्थान पर केशव महाविद्यालय रहा। राजधानी कॉलेज ने इस्लामिक आतंकवाद व अर्बन नक्सल पर प्रस्तुति दी जबकि केशव महाविद्यालय के द्वारा खुदकुशी जैसे महत्वपूर्ण विषय को उजागर किया गया। मतदान जागरूकता के लिए श्यामलाल कॉलेज को विशेष पुरस्कार दिया गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कला, मानवीय विवेक का परिष्कार करती है। ऐसे कार्यक्रम छात्रों को रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं नाटककार व पूर्व आईएएस दयाप्रकाश सिन्हा ने छात्रों को वामपंथियों द्वारा सांस्कृतिक विरासत, कला, नाटको को दूषित करने के कुत्सित प्रयास से परिचित करवाया। ■

महात्मा गांधी की सार्धशती पर विशेष आलेख श्रृंखला - 6

धर्मपथ और शांतिपथ के चौराहे पर गांधी

|डा. जयप्रकाश सिंह|

पिछली कुछ सदियों से भारत जब भी धर्म और शांति के चौराहे पर खड़ा होता है तो वह खुद को असमंजस की स्थिति में पाता है। निर्णायक क्षणों में असमंजस की स्थिति में फंसने की यह मानसिकता भारत में गहरे तक धंसी हुई है और इसके कारण भारत और भारतीयता को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।

हैरत की बात यह है कि बदलावों के दौर से गुजर रहे इस देश में अब भी यह मानसिकता यथावत बनी हुई है। अब भी यह देश धर्म और शांति के चौराहों पर खुद को असहज और असहाय महसूस करता है। पुलवामा के बाद उभरा परिदृश्य इस बात का हालिया उदाहरण है। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने के बाद जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था तब मीडिया और नागरिक समूहों के एक धड़े ने एकाएक शांति का राग अलापना शुरू कर दिया। शांति का राग बुरा नहीं है लेकिन हर राग का एक प्रहर होता है, एक समय होता है। बेसमय का राग बेसुरा तो होता ही है , नुकसानदायक भी। जब सत्य और धर्म का प्रश्न मुंह बाए खड़ा हो तो भारतीय परंपरा शांति – अशांति का कसौटी को गौण मानती रही है। शांति की परिधि में धर्म हमेशा चक्कर लगाए , यह जरूरी नहीं है। धर्म पंथ पर शांति - अशांति के बजाय देश – काल – पात्र का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पथ पर कुछ भी अस्पृश्य नहीं है। देशबोध और कालबोध के हिसाब से प्राथमिकता – सूची में ऊपर से नीचे होता रहता है।

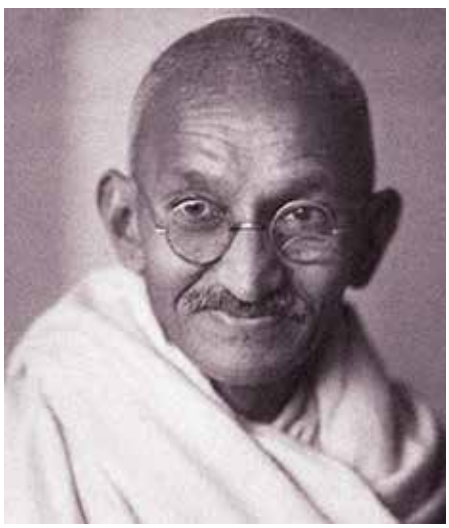

भारतीय परंपरा में निर्णय लेने की मुख्य कसौटी धर्म और न्याय है, शांति और समझौते नहीं। धर्म यदि शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि धर्म के मार्ग में शांति बाधा बनकर खड़ी हो जाए तो धर्म उस बाधा को ध्वस्त कर आगे बढ़े, यह परंपरा का आदेश है।

रामायण और महाभारत का यही संदेश है, राम और कृष्ण की यही सीख है। इस बात को विस्मृत नहीं किया जा सकता कि धर्म के बजाय यदि शांति को तरजीह दी गई होती तो रामायण और महाभारत कभी नहीं घटित होते। गीता का तो संपूर्ण उपदेश ही प्राथमिकता सूची में धर्मपथ को शांतिपथ से ऊपर रखने के लिए दिया गया है। इस परंपरा के आलोक में और ऊहापोह की वर्तमान भारतीय मानसिकता के संदर्भो में गांधी के आकलन की यथार्थ पृष्ठभूमि तैयार होती है।

गांधी ने मानसिक स्तर पर अपने जीवन का बड़ा हिस्सा धर्मपथ और शांतिपथ के इस चौराहे पर बिताया। उनके निर्णयों और आदर्शों पर इस चौराहे की ऊहापोह की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वह सत्यकाम भी है और शांतिकाम भी। उनके चिंतन की मूल समस्या यह है कि वह सत्य को शांति की परिधि में ही स्वीकार करने को तैयार है। मानवीय प्रवृत्तियां और दुनियावी गतिविधियां तो यही बताती हैं कि सच को शांति के दायरे में नहीं समेटा जा सकता। गांधी जब यह कहते हैं कि 'सत्य ही ईश्वर है' तो वह इस बात स्वीकार कर रहे होते हैं कि निर्णय की अंतिम कसौटी सत्य है लेकिन जब वह यह कहते हैं कि अहिंसा एक मात्र रास्ता है तो वह सच की परिधि निर्धारित कर देते हैं। सच और शांति

के अन्तर्सम्बन्धों की यह जटिलता, गांधी चिंतन को विशेषता देती है और कुछ हद तक कमजोर भी बना देती है।

गांधी ने भारतीय परंपरा में बदलाव करते हुए शांति को सत्य से ऊपर रखने की कोशिश की। हालांकि वह सत्याग्रह करते दिखते हैं लेकिन केन्द्र में अहिंसाग्रह होता है।

मूल्यों और आदर्शों को हम परंपरानुसार यथाक्रम फिर से व्यवस्थित कर सकें तो यह गांधीवादी चिंतन का परिष्कार होगा और परंपरा का पोषण भी। आज की परिस्थितियों में यह देश और समाज दोनों के लिए अधिक आवश्यक कर्म बन गया है। हां, इस कार्य को गांधीवाद के सतही विरोध के तौर पर नहीं लिया जा सकता है और न ही लिया जाना चाहिए। क्योंकि यह स्व-परिष्कार है और गांधी स्व-परिष्कार की सतत प्रक्रिया के सबसे बड़े प्रतीक। ■

(लेखक हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं।)

केंद्र सरकार के अध्यादेश से पीड़ितों को मिला न्याय : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक कैडर में आरक्षण अध्यादेश 2019 के माध्यम से विश्वविद्यालय में नियुक्ति संबंध के विषय में विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए 200 प्वाइंट रोस्टर को लागू करने के अध्यादेश का स्वागत किया। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा विभाग को एक इकाई मानते हुए १३ प्वाइंट रोस्टर लागू करने संबंधी निर्णय पर केंद्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दायर याचिका एवं पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। अभाविप निरंतर आरक्षित वर्ग के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से विभाग एक इकाई, 13 प्वाइंट रोस्टर के विरूद्ध और विश्वविद्यालय एक इकाई, 200 प्वाइंट रोस्टर के समर्थन में अध्यादेश लाने की मांग कर रही थी।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभाग एक इकाई मानते हुए 13 प्वाइंट रोस्टर को लागू करने के समर्थन के कारण आम जनमानस में निराशा का भाव था। अभाविप का स्पष्ट मत रहा है कि 200 प्वाइंट रोस्टर में आरक्षित वर्ग को संवैधानिक तौर पर अपेक्षित आरक्षण प्राप्त हो पाएगा। इसलिए पिछड़े समाज के हित में 200 प्वाइंट रोस्टर का लागू होना आवश्यक है। परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नेहा मार्डी ने कहा कि आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। इसका अभाविप स्वागत करती है। ■

जंगल से जनजातियों को बेदखल करने संबंधी अदालत के फैसले पर अभाविप ने की पुनर्विचार करने की मांग

उच्चतम न्यायालय के एक फैसले में सोलह राज्यों की वनभूमि से अनुसूचित जनजाति एवं वनवासियों को बेदखल करने की बात कही गई है। न्यायालय के इस फैसले से जंगल में रहने वाले जनजाति पशोपेश में आ गये हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। फैसले पर टिप्पणी करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा है कि पक्षकारों ने माननीय न्यायालय के समक्ष सही स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं रखा जिसके परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल से जनजातियों एवं वनवासियों के अधिकारों को छीना जाना अनुचित है तथा उनके पक्ष को न्यायालय के समक्ष पेश करने में कहीं न कहीं कोताही हुई है। अभाविप न्यायालय से विनम्र आग्रह करती है कि जनजातियों तथा वनवासियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। ■

भारत जैसी पारिवारिक संरचना मुझे कहीं नहीं दिखी : माधुरी सहस्त्रबुद्धे

पहली बार चार भारतीय माताओं ने दुनिया को भारत का महत्त्व बताने के लिए वाहन से 22 देशों – नेपाल, चीन, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कीस्तान, ईरान, अजहरबाइजान, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीटजरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम) की यात्रा की। इस यात्रा का नाम 'मदर्स ऑन व्हील' दिया गया था, जिसे 10 सितंबर 2018 को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 22 देशों की यात्रा कर लौटी 'मदर्स ऑन व्हील' की नेत्री माधुरी सहस्त्रबुद्धे से 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के सहायक संपादक अजीत कुमार सिंह ने उन देशों की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक संरचना, माताओं की स्थिति, भारत के प्रति उनका विचार संबंधित विषयों पर बात की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश –

'मदर्स ऑन व्हील' यात्रा के बारे में बतायें ?

'मदर्स ऑन व्हील' यात्रा की शुरूआत 10 सिंतबर को नई दिल्ली से हुई। पहली बार भारत की चार माताएं वाहन से विदेशी माताओं की स्थिति को जानने के लिए यात्रा कर रही थी, जिस कारण इस यात्रा का नाम हमलोगों ने 'मदर्स ऑन व्हील' दिया। हमारे साथ तीन महिलाएं माधुरी सिंह तोमर (ग्वालियर), उर्मिला जोशी (पुणे) और शीतल देशपांडे (पुणे) थीं। शीतल को छोड़कर हम सभी 50 से अधिक उम्र के थे। इस यात्रा का उद्देश्य दुनिया को भारत के महत्त्व के बारे में बताना और विदेशों में बच्चों की परवरिश में माताओं की भूमिका को जानना था। हमलोंगों की योजना थी कि यात्रा की शुरूआत पाकिस्तान से करें लेकिन वहां से अनुमति न मिलने के कारण, हमलोगों ने अपनी यात्रा की शुरूआत चीन से की। चीन में हमलोगों को किसी भी स्थानीय महिलाओं से बात करने नहीं दिया गया। चीन से कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस आदि होते हुए यूके की राजधानी लंदन पहुंची और लंदन से पुनः भारत लौटी। कुल 60 दिनों में हमलोगों ने 23,657 किलोमीटर यात्रा की। इस दौरान हमलोगों ने चीन को छोड़कर लगभग 25 स्थानों पर उस देश की माताओं के साथ संवाद किया और उन्हें भारत की संस्कृति के बारे में बताया, उनलोगों ने भी अपने देश की संस्कृति,सामाजिक संरचना इत्यादि को हमलोगों के साथ साझा किया। कजाकिस्तान से हमलोगों ने अपने दम पर यात्रा की क्योंकि चीन में हमलोगों के साथ वहां का गाइड था, नेपाल में लगभग सभी लोग हिंदी बोलते हैं जिस कारण वहां पर भी कोई परेशानी नहीं आई लेकिन चीन की सीमा पार करने के बाद हमलोगों को भाषा एवं डॉलर वगैरह की समस्याएं आई। यात्रा के दौरान कजाकिस्तान के एक युवक ने हमलोगों की काफी सहायता की, डॉलर एक्सचेंज से लेकर भोजन व होटल को ढूंढने तक। यह यात्रा हमलोगों के अनुमान से बिल्कुल अलग निकला।

विदेशों में माताएं अपने बच्चों की परवरिश किस प्रकार से करती है, क्या उन देशों में महिलाओं की स्थिति भारत से भिन्न है ?

विदेशों में भी माताएं अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती है जितनी हिन्दुस्तानी माताएं। अधिकतर देशों में सिंगल मदर सिस्टम, लिव इन रिलेशनशिप का रिवाज है। यहां तक तो ठीक है लेकिन कुछ देशों की स्थिति बहुत ही नारकीय है। महिलाओं को उसके पुरूष मित्र गर्भवती होते ही छोड़ देते हैं साथ ही उसके माता – पिता भी उन्हें घर से निकाल देते हैं। जिस कारण कई बार उन्हें वेश्यावृति के लिए मजबूर होना पड़ता है, इन माताओं की औसतन उम्र 16 – 20 साल थी। उनके बच्चे अनाथालय में पलते हैं। उन देशों में भारत की तरह शादी, सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यौन संतुष्टि तक सीमित होती है। पुरूष को महिला से मन भर गया तो उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, इसी तरह महिला भी पुरूष को छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है। एक अनुभव शिविर में एक बच्चा मिला, उसने अनुभव साझा किये, जिसे सुनकर हमलोग आश्चर्य

में पड़ गये। बच्चे के मुताबिक उसे नहीं पता उसकी माता – पिता कौन है ? जब मैंने पूछा कि ऐसा कैसा हो सकता है, तो बच्चे ने मुझे बताया कि मेरे जन्म के बाद मेरे माता – पिता अलग रहने लगे, उसके बाद माता ने दूसरी शादी कर ली, पिता ने भी दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी... वर्तमान में वे लोग किनके साथ हैं और कितनी शादी कर रहे हैं नहीं पता। यात्रा के दौरान हमलोगों ने अनुभव किया कि कमोवेश सभी देशों की महिलाएं तनाव में दिखती है। संवाद कार्यक्रम के दौरान एक माता से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने जो दर्द बयां किया वह काफी पीड़ादायी है। महिला के मुताबिक शादी के बाद उसका बच्चा हुआ, बच्चे के कुछ ही महीने बाद उन पर पति ने पैसे कमाने का दबाव डालना शुरू कर दिया, चूंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आर्थिक जिम्मेवारी पति नहीं पत्नी निभाती है। पत्नी अपने नन्हें बच्चे को छोड़कर कमाने के लिए दूसरे देश में चली गई, इस दौरान उनके लिए संवाद का माध्यम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया था।

अपने बच्चों की परवरिश के लिए हर महीने वो अपनी सारी कमाई पति को भेजती रही। चार साल बाद जब वो अपना घर लौटी तो उसके पति दूसरी शादी कर चुके थे। बच्चे के बारे में पता करने पर जानकारी मिली कि वह सरकारी अनाथालय में पल रहा है, जब वह अपने बच्चे से मिली उसने अपनी मां को पहचाना तक नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं, उस समय एक मां पर क्या बीत रहा होगा। ऐसे अनेकों घटनाएं है जिसे जानकर आप हैरान हो जायेंगे। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर माताएं 14 साल के बाद अपने बच्चों को बोझ मानने लगती है ठीक इसी प्रकार बच्चे भी अपने माता – पिता को बोझ मानते हैं। यात्रा के दौरान एक विकसित देश में भारतीय दूतावास की एक सहेली के साथ एक घर में जाना हुआ वहां बातचीत के दौरान कहा कि आज घर में रहने की बारी मेरे पति की है लेकिन मैं रह गई। बातों – बातों में मैंने पूछा घरेलू काम – काज में आपके पति कितना सहयोग करते हैं तो वह बोली कि मात्र पांच प्रतिशत। मेरी सहेली ने मुझसे हिन्दी में कहा कि पूछो न! घर के काम – काज में आप कितना समय देती है तो मैंने उक्त महिला से पूछा तो उनका जवाब था 25 मिनट वह भी रोबोट, क्लीनिंग मशीन की जांच के लिए। उन्होंने कहा कि हमलोग से अच्छा तो Scandinavian Countries हैं जहां पर महिलाओं को काम भी नहीं करना पड़ता है।

आपने अभी Scandinavian Countries का जिक्र किया, कृपया इन देशों की सामाजिक संरचना और महिलाओं की स्थिति के बारे में बतायें।

Scandinavian Countries में महिलाओं को घर में रहने के बदले सरकार के द्वारा सैलेरी दी जाती है। यह व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन इसके Extreme (अति) को सुनकर आश्चर्च में पड़ गई। एक बार एक माता की तबीयत ठीक नहीं थी जिस कारण अपने बच्चे को नियत समय पर दूध नहीं पिला पाई तो उसके पति ने इसकी शिकायत सरकार से कर दी और उसकी सैलेरी कटवा दी। वहीं एक बार अभिभावक ने अपने बच्चे को स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उसे मनपसंद भोजन नहीं दिया तो बच्चे ने अपने माता – पिता की शिकायत पुलिस से कर दी कि मेरे अभिभावक मुझे प्रताड़ित करते हैं जिस कारण उस दंपत्ति को जेल की हवा खानी पड़ी। आपने समाचारों में एक हिन्दुस्तानी एनआरआई दंपत्ति की कहानी तो पढ़ी ही होगी कि उनके बच्चे औसत से ज्यादा मोटा होने के कारण किसी ने पुलिस से यह कहते हुए शिकायत कर कर दी थी कि इनके अभिभावक अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते। पुलिस ने उनके बच्चे को उनसे छीनकर सरकारी अनाथालय में डाल दिया।

विदेशियों के मन में भारत के प्रति क्या विचार है ?

मैं जिन 20 - 22 देशों में गई, वहां के लोगों की बात करूं तो वे लोग भारत की पारिवारिक संरचना और संस्कृति से काफी प्रभावित हैं। वे सभी (कुछेक को छोड़कर) मुक्त कंठ से भारतीय संस्कृति की सराहना करते हैं। संवाद के कारण औसतन यह सवाल होता था कि भारत में पारिवारिक संरचना की मजबूती का कारण क्या है ? कुछ लोगों ने भारत की गंदगी और ट्रैफिक की भी शिकायत की। उनलोगों का कहना था कि भारत में गंदगी बहुत है, लोग जहां – तहां थूक देते हैं। ट्रैफिक की बहुत समस्या है। ■

परिवर्तन की राह पर पश्चिम बंगाल

विक्रांत खंडेलवाल

बचपन में जब सबसे पहले पं. बंगाल के कोलकाता शहर का नाम सुना तो जानकारी में आया था कि वहां स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ है । उनका बचपन, शिक्षा, प्रारंभिक आध्यात्मिक यात्रा भी उसी कलकत्ते की गलियों में हुई है। जब सुभाष चन्द्रबोस का नाम सुना तब भी बंगाल की ऐतिहासिक विरासत याद आयी । वन्दे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चन्द्र चटर्जी इसी बंगाल की साहित्य परंपरा को राष्ट्रीय पहचान देने वाले महापुरूष रहे हैं। सुदूर जम्मू कश्मीर में जाकर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी मिट्टी के सुपुत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वले गुरुवर रविन्द्र नाथ टैगोर ने इसी बंगाल को अपना कर्मभूमि भी बनाया। आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले अनेक महापुरूषों की जन्मस्थली, कर्मस्थान के साथ – साथ बंगाल आजादी के आंदोलन की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। हिन्दू राष्ट्रवाद बंगाल की संस्कृति परंपराओं का अभिन्न रक्तकण है। डा. गोपालकृष्ण गोखले ने कभी बंगाल की प्रज्ञा पर विश्वास करते हुए कहा था कि 'बंगाल जो आज सोचता है वही भारतवर्ष कल सोचता है।'

हिन्दू राष्ट्रवाद की भावनाओं के ज्वार में बंगाल ने आध्यात्मिकता को कहीं से भी पीछे नहीं छोड़ा। देश में जब कभी भी, जहां कहीं भी दुर्गा पूजा की बात होती है तो बंगाल प्रथम स्थान पर होता है। काली माता, सरस्वती माता के साथ – साथ बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा ने सभी देवी देवताओं को अपने जीवन में स्थान दिया है। उत्सवों, त्यौहारों को वहां के लोग बहुत ही भव्य तरीकों से उत्साहपूर्वक ढंग से मनाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, विश्वभारती, इस्कान मंदिर जैसी अनेक अनेक संस्थाएं बंगाल में अपना राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अभियान चला रही है। इन सभी उपरोक्त कारणों से मन में बंगाल की छवि हिन्दुत्व, राष्ट्रवाद, आध्यात्मिकता की जन्मस्थली जैसी बनी है। लेकिन वर्तमान समय में बंगाल के जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि बंगाल की भूमि पुनः पुनः शस्य श्यामला बन हिन्दु राष्ट्रवाद के उभार की जमीन तैयार कर रही हो। गत कुछ 35-40 वर्षों में जिस प्रकार अधिकांश समय विदेशी विचार वाली कम्युनिष्ट पार्टी के पास सत्ता रही है। बंगाल में बड़े पैमाने पर पड़ोसी बांग्लादेश से घुसपैठ हुई है। इस कम्युनिष्ट – मुस्लिम गठजोड़ ने बंगाल प्रज्ञा को कम्युनिष्ट विचारों का गुलाम बनाने की योजना ने बंगाल को विकास की दौड़ में वर्षों पीछे धकेल दिया है और जहां विकास नहीं होता, रोजगार नहीं होता वहां बुराईया जन्म लेती ही है। आज का बंगाल इसी परिणाम स्वरूप मिली अराजकता का शिकार है। वर्तमान समय में बंगाल की छवि देश में एक अराजक, आशांत प्रदेश की बन रही है। कुछ घटनाओं से हम वहां की स्थिति समझ सकते हैं।

- 4 जनवरी कालियाचक, मालदा थानें को लूटकर जला दिया गया ताकि गत वर्षों में उन कट्टरपंथियों द्वारा किये गये अपराधों को छुपाया जा सके।
- नदिया के जुरानपुर में डोल सम्प्रदाय के तीन व्यक्तियों को मुस्लिम गुण्डों ने दिन दहाड़े हमला करके मार डाला।
- दिसंबर 16 में धूलागढ़ में सुनियोजित तरीके से हिन्दू समाज पर आक्रमण किये।
- गत वर्ष दुर्गा पूजा पर एक 17 वर्षीय दलित बालिका पर ऐसिड बम से हमला कर उसे इसलिए मारा डाला क्योंकि उसने 50 वर्षीय विवाहित इमाम अली शेखसे विवाह करने से इंकार कर दिया।
- खड़कपुर में खटीक समाज के रोहित तांति को कट्टरवादियों ने लोहे की छड़ से पीट –पीट कर मार डाला।
- 11 अप्रैल 17 को मालदा में 6.96 करोड़ के नकली नोट का पकड़ा जाना।
- बंगाल के खगडागढ़, पिंगला सहित कई स्थानों पर हुए बम विस्फोट की जांच में जे. एम. बी. (जमातउल-मुजाहिदिन-बांग्लादेश) व अन्य आतंकी संगठनों की सक्रियता की पुष्टी हुई है।

साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी, गौधन की तस्करी आदि का अवैध कारोबार बंगाल की धरती पर आम बात है। पता नहीं अवैध धंधों, गतिविधियों, आतंकवाद आदि का मुस्लिम समाज के साथ क्या गठजोड़ है । कही सुना

है कि 'हां ये सही है कि हर मुसलमान आतंकी नहीं है पर पता नहीं हर आतंकी मुसलमान क्यों निकलता है।' और उस पर जो इनको कम्युनिष्टो और बाद में मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार करने वाली इस तृणमूल पार्टी और सरकार के साथ लगती बांग्लादेशी सीमा इनके लिए स्वर्गगाह बनी हुई है।

वर्तमान तृणमूल सरकार की मुस्लिम परस्त नीतियों के कारण सत्ता द्वारा बंगाल में हिन्दुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे –

- दुर्गापूजा पर मोहर्रम के कारण प्रतिमाओं के विसर्जन का समय असामान्य रूप से कम कर दिया, फिर मा. उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से राहत मिली। इस वर्ष फिर कानून व्यवस्था का हवाला देकर उस दिन विसर्जन को ही प्रतिबंधित कर दिया।
- राज्य सरकार एक ओर राष्ट्रभक्ति के संस्कार देनेवाली विद्यालयों को बंद करने की धमकी दे रही है वहीं दूसरी ओर कुख्यात सिमुलिया मदरसा जैसी हजारों संस्थाओं की ओर आंखे मुंदे हुए है। तथ्य की बात ये है कि बंगाल राज्य में गत वर्ष उद्योगों के विकास हेतु मात्र 2154 करोड़ रूपये दिये गये, वहीं मदरसा शिक्षा का बजट 2815 करोड़ कर दिया है।
- शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रों में मुस्लिम तुष्टिकरण एवं जिहाद के चलते पाठ्यपुस्तकों का राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर इस्लामीकरण किया जा रहा है।
- विद्यालयों में हाली में राज्य सरकार ने मिलाद-उन-नबी (मोहम्मद साहब क जन्मदिवस) मनाने का आदेश दिया वहीं दूसरी ओर हिन्दू त्यौहारों पर रैली, संगोष्ठी आदि प्रतिबंधित की जा रही है।

सत्य तो ये है कि आज पश्चिम बंगाल का पुलिस प्रशासन नारियों पर अत्याचार करने वालों का धर्म देखकर ही अपनी भूमिका तय करता है।

आज बंगाल में बंगाली संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, त्योहार सबके समक्ष भयानक चुनौती खड़ी है। पं. बंगाल में मुस्लिम परस्त नीतियों के कारण मूल बंगाली हिन्दू समाज पलायन को मजबूर है। साथ ही रोजगार नहीं होने के कारण अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो रहा है। वहीं सत्ता के मद में चूर ममता सरकार जन भावनाओं के साथ राजनीति खेल रही है। गत वर्ष रामनवमी के अवसर पर पूरे पं. बंगाल में निकले बड़े जुलूसों, शोभायात्राओं समारोह के कारण यहां हो रहे हिन्दुत्व के उभार को दबाने के लिए गौरखा भाषा के स्थान पर वहां पर बंगाली भाषा की अनिवार्यता की शर्त जोड़कर समूचे दार्जलिंग को अनिश्चतता की आग में जलने को छोड़ दिया ताकि बंगाली भाषा के प्रति स्वाभाविक प्रेम को वोट के रूप में बदल कर हिन्दुत्व के उभार को रोका जा सके। हाल ही में 15 अगस्त को केन्द्र सरकार द्वारा उत्सव मनाने की योजना को ठुकराकर ममता सरकार ने एक बार फिर अंधविरोध का रास्ता अपनाया है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है।

> वर्तमान समय के इस दौर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस प्रकार से केन्द्र सरकार के कामकाज की सफलता के हर मुद्दे पर भड़क रही है। उससे यही कहावत उन पर सटीक बैठती है कि दिया बुझने से पहले बहुत भभकता है। जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व ममता दी ने कम्युनिष्टों के 35 वर्ष पुराने कुशासन को उखाड़ फेंका था तब से उसे लगता है कि बंगाल में उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता।

वर्तमान समय के इस दौर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस प्रकार से केन्द्र सरकार के कामकाज की सफलता के हर मुद्दे पर भड़क रही है, उससे यही कहावत उन पर सटीक बैठती है कि दिया बुझने से पहले बहुत भभकता है। जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व ममता दी ने कम्युनिष्टों के 35 वर्ष पुराने कुशासन को उखाड़ फेंका था तब से उसे लगता है कि बंगाल में उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और तौ और वो अब विपक्षी दलों की एकता के दम पर केन्द्र की सत्ता हथियाना चाहती है लेकिन उसने प्रकृति के उस सिद्धांत को भूला दिया कि 'परिवर्तन संसार का नियम है' और आज केन्द्र की सत्ता और मोदी विरोध में वह इतनी बौखला गई है कि लोकतांत्रिक लड़ाई की बजाय अलोकतांत्रिक हथकंडे अपनाने लगी है। ममता की बौखलाहट के इस दौर में परिषद् के सामान्य छात्र आंदोलन के डर से पुलिस द्वारा गोलिया चलवाना, केन्द्र की आयुष्मान भारत जैसी अभूतपूर्व चिकित्सा योजना से बंगाल की जनता को वंचित रखना आदि अनेक प्रकार की दुर्घटनायें बंगाल में हो रही है।

हाल ही में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव

कुमार को बचाने के लिए उन्होंने संविधान को भी ताक पर रख दिया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रही है और उसे इस मामले में किसी से भी पूछताछ करने का अधिकार है और वो उसी अधिकार का उपयोग कर रही थी। राजीव कुमार एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं इसलिए उनको कई बार सम्मन भेज कर बुलाया गया था लेकिन सत्ता के संरक्षण के चलते उन्होंने सीबीआई की उपेक्षा लगातार की थी एवं वे जांच में सहयोग देने को भी तैयार नहीं थे। भारतीय इतिहास में आज तक जो कभी नहीं हुआ वह बंगाल में हो गया कि सीबीआई अधिकारी किसी से पूछताछ करने जाये और उनको स्थानीय पुलिस गिरफ्तार कर लें लेकिन ममता राज में यह सब हो गया। पं. बंगाल की ममता दी केन्द्र की सरकार का विरोध करते करते यह भी भूल गई कि ये पूरा मामला सीबीआई और पुलिस के बीच का था लेकिन ममता इसमें केन्द्र का हाथ बताते हुए धरने पर बैठ गई। इसके बाद राजैनेतिक ड्रामा तो पूरे देश ने देखा ही है कि किस प्रकार देश भर के हारे थके ठगबंधन नेताओं की जमात पं. बंगाल में जुटी थी। सवाल यह है कि बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता एक पुलिस अधिकारी के लिए संविधान के खिलाफ हो गई। वास्तव में ममता बनर्जी बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो इस समय बुरी तरह भयभीत है।

आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर बड़ी संख्या में हिन्दुओ के प. बंगाल में आने के बाद भी यहां की हिन्दू जनसंख्या 1951 में 78.48 के मुकाबले वह 2011 में 70.54 रह गई है। हम देख सकते हैं कि पं. बंगाल में किस प्रकार अवैध मुस्लिम घुसपैठ हुई है साथ ही जनसंख्या वृद्धि भी हुई है। मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया है कि बंगाल की माटी और मनुष्य का ऐतिहासिक योगदान इस भारत वर्ष के निर्माण में रहा है। यह स्वर्णिम इतिहास, महापुरूष यहां की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विचारधारा हमें सुनहरे भविष्य की ओर इंगित कर रही है। वर्तमान समय का बुरा दौर, बुरे लोग, बुरी घटनायें सब पीछे छूटेगी। इतिहास अपने आपको दोहराता है । जब जब धर्म की हानि हुई अत्याचार बढ़ा तब तब धर्म की रक्षार्थ कोई आगे आया है। वर्तमान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 'जन' ही देवता है। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां, अत्याचार, आतंकवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां, अकर्मण्य प्रशासन सभी को रोकने, सुधारने और संविधान की रक्षा के लिए वर्तमान समय में जनजागरण ही एक मात्र उपाय है। कहते हैं आंदोलन केवल सड़कों पर नहीं होता बल्कि व्यक्ति के मन में वर्तमान व्यवस्था, नीतियों, घटनाओं, निर्णयों के विरोध में विचार भी आता है तो वो विचार हमारे मन को आंदोलित करता है और उस विचार को हम आगे प्रसारित करते हैं तो वो आंदोलन प्रारंभ होता है।

आज बंगाल, बंगाली संस्कृति, बंगाली भाषा को बचाने का ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन प्रत्येक देशवासी से सहयोग का आह्वान कर रहा है। आज बंगाल की धरती पर इस सामाजिक परिवर्तन अभियान में सहभागी प्रत्येक संस्था, व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। इस आंदोलन का एक बड़ा संकट संवाद माध्यम है। आज राज्य में संवाद माध्यम भय और लोभ के वशीभूत सत्य को उजागर नहीं करता। कोई राष्ट्रीय चैनल कुछ दिखाने का साहस भी करता है तो उसके विरूद्ध मिथ्या एफआईआर दर्ज की जाती है। एक प्रकार से ऐसा लगताहै कि पं. बंगाल में पत्रकारिता की नैतिक मृत्यु हो गई हो।

पं. बंगाल में वर्तमान व्यवस्था के विरोध में अभियान, आंदोलन समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चल रहा है। शिक्षा, धर्म, मजदूर, किसान, वनवासी सहित राजनैतिक क्षेत्र भी इस अभियान लगा है। आज बंगाल में होने वाले अत्याचारों से सर्वाधिक प्रभावित वहां का अनुसूचित जाति समाज है। बेरोजगारी से पीड़ित गरीब लोग है। बुरी घटनाओं की शिकार महिलायें होती है। उद्योग जगत के प्रति नकारात्मक नीतियों के कारण बड़े उद्योगपति वहां से पलायन को मजबूर किये जा रहे हैं। मदरसों को संरक्षण की आड़ में सरकारी एवं नीति विद्यालयों की कमर तोड़ी जा रही है। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार तथा सरकारी तंत्र के संरक्षण में चलने वाली अनेक राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता विरोधी संस्थायें राष्ट्रवाद के विचार को अपमानित करने का की अवसर नहीं छोड़ रही है। पं. बंगाल में इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की अगुवाई करने वाली संस्था, व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक देशवासी देशभर में रहनेवाली प्रवासी बंगाली समाज से इस परिवर्तन आंदोलन से जुड़ने का आह्वान करती है और विशेष रूप से बंगाल की आवाज को देश की आवाज बनाये अपनी – अपनी शक्ति समर्थ के अनुसार जन जागरण का हिस्सा बनें ताकि हम अपनी मां, माटी , मानुष को बचाने के अभियान में सफल हों। ■

75 years of Hoisting Tiranga in Andaman and Nicobar Islands – Saga of Guts and Glory

DR KANWAR CHANDERDEEP SINGH

The day of 30th December, 2018 has been a landmark day not only for the Andaman and Nicobar Islands but for the whole nation from several aspects. Firstly, it was the day when after a long time prime minister of the country visited the remote Islands which often remained neglected, at least politically. Secondly, this day and year marked the platinum jubilee celebrations of the hoisting of the tricolour in the Islands by one of the tallest national heroes Netaji Subhash Chandra Bose. Thirdly, the capital city of Port Blair got its tallest flag mast and thus made an addition to several points of attraction primarily to those which instil national fervour among the people. Fourthly, from the strategic point of view, the visit of prime minister and hoisting of national flag added another dimension to Bharat's 'Act- East' policy. And lastly, the visit also resulted into the change of colonial names of few important Islands by replacing them with the nationalist names. I will deal with these different dimensions in the subsequent paragraphs in more elaborate manner. However, one common thread the bound all the aspects is the immense symbolic as well the real importance of the idea of nationalism and its need to instil in the hearts of the people.

The Andaman and Nicobar Islands are not merely a geographical entity but the south eastern sentinel of India having immense historical and strategic importance. But for long, the Islands remained a neglected piece of land primarily because of the fact that Indian polity still hovers around the vote bank politics and the number of seats in the parliament. The region doesn't fit in the profitable bracket of electoral politics. But the political situation changed drastically after 2014 with prime minister Modi at the helm of affairs the political mindset too underwent paradigmatic change. The maiden visit of PM signifies that change. No longer would the regions that are politically less significant be ignored at the altar of electoral gains. Every region, near or far, is the equal stakeholder in the growth story of Bharat and must get its due share. The people must feel one with the rest of the nation and the alienation caused by the geography and political neglect must not hamper the spirit of Akhanda Bharat. The visit of Modi ji empathically brings home this point.

Historically speaking, the day of 30th December 1943 was marks a glorious chapter in the annals of our history as for the first time Tiranga fluttered in the free skies of Port Blair and Azad Hind Government (Arzai i Hukumat i Azad Hind) was formed. To acknowledge the contribution of our forgotten hero towards the liberation of our motherland is nothing but a small homage to the unwaivered spirit of Netaji Subhash Chandra Bose. His contribution towards the national movement in spite of remaining out of the Congress can be captured from what Mahatma Gandhi had said about him. He was called 'the Prince among Patriots" by him. It was Netaji who despite having ideological differences with the Gandhi ji called him 'the father of our nation'. The legacy of Netaj and his Azad Hind Fauj (Indian National Army) was cleverly whitewashed by the ruling dispensation of free India under Jawaharlal Nehru for the reasons that are gradually coming in public sphere after the de-classification of many classified files pertaining to Netaji and Azad Hind Fauj. The so called historians who had long sung paeans for Nehru-Gandhi and their lineage and had shamelessly indulged in intellectual dishonesty would now be scrutinized and questioned for undermining of the contribution of Netaji. Thus, finally under

this government the national hero is getting what was long due from a grateful nation.

The hoisting of tallest flag in these Islands has many meanings. For the eternal naysayers and pessimists it might have been outright symbolism and wastage of the national resources. However, it goes beyond the just symbolic and touches the right chords of heart. It reemphasizes the sovereignty and integrity of the proud nation of 1.3 billion from the remotest corners of the nation amidst the vast expanse of the ocean. If a majestic view of waving tricolour doesn't leave you with goose bumps then what sort patriot you are? Many a times symbols speak louder than the actions and its detractors should learn to live with it. Not only this, as the Islands have been fast emerging as the global tourist destination such a national landmark serve as must see places in the tour itinerary and potentially contribute to the state exchequers. It remains a win-win situation both ways.

The visit would have a lasting impact on the Bharat's Act East policy because the Islands stand in the immediate vicinity of our south East Asian neighbours like Malaysia, Indonesia, Thailand and Myanmar. In the times to come the Islands are bound to play a much larger and decisive role in the geo-politics of Indian Ocean especially at a time when China is emerging as threat to the peace and tranquillity of countries of south East Asia. These countries are naturally finding a trustworthy friend in Bharat to counter the Chinese threat. The Islands oversee the Gulf of Malacca, one of busiest sea trade routes and a lifeline of Chinese oil supplies from the Gulf, and this naturally gives an edge to Bharat to counter any Chinese mis-adventure in future. The pursuance of such a policy with Andaman and Nicobar Islands as a launch pad immensely enhances its significance.

Finally, some of the colonial vestiges in the form of British names of several Islands too got the long pending attention of the government. The predecessor governments just like forgetting Netaji and his glorious legacy, also conveniently ignored that Andaman and Nicobar too has become independent like the rest of India. If Madras can become Chennai, Bombay becomes Mumbai, Calcutta becomes Kolkata, Bangalore becomes Bengaluru then what on earth stopped the earlier governments from renaming those Islands which are known by the British names? Indian mentality has long been a classic case of 'Stockholm Syndrome' i.e. developing love and sympathy for one's own tormentor. In this case the invaders, murderers, looters and plunderers. The current prime minister ultimately drew the curtains on some of the important Islands especially those having tremendous tourism significance namely, Havelock, Neil and Ross. Now Havelock Island has rightfully become Swaraj dweep, Neil Island became Shaheed dweep and Ross Island became Netaji Subhash Chandra Bose dweep. Even seventy years of British departure from Bharat we still remain under the colonial hangover and such a step by the government will go a long way in instilling self pride among the people. However, there is still a long path to cover to decolonise the consciousness of this nation.

The major takeaways of the historical visit of Modi ji may not become tangible right away and perhaps would take some time to show the expected results. But the message that it intended to deliver was delivered loud and clear. We celebrated the sovereignty, integrity and inherent strength of our modern Bharat the foundation of whose was laid by indomitable Netaji exactly 75 years back. There were odds against the nation then and there are odds against us now but the undying spirit of this ancient land will overcome all. As the prime minister is leading this nation to glory from the front, we the proud youth of this land, must, with all our strength and conviction make this nation Vishwa Guru again. That would be our tribute to not only Netaji but to all the great heroes of the past who lived and died for this motherland. ■

(Author is Head of Department Historical Studies, JNRM, Andaman and Nicobar Islands.)

पुलवामा हमला और भारत की कार्रवाई पर विपक्ष की प्रतिक्रिया कितनी उचित?

14 फरवरी 2019 को जम्मू – श्रीनगर राजमार्ग पुलवामा के लेथपोरा के नजदीक ढ़ाई हजार से अधिक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को ले जा रहे वाहनों के जत्थे पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले में 49 से अधिक जवान शहीद हो गये, जबकि 35 से अधिक जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलवामा हमले के बाद जवानों को खोने का गम और हमले के जिम्मेवार पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में कार्रवाई किये जाने की मांग की गई। भारतीय वायु सेना ने पुलवामा हमले के ठीक तेरहवें दिन बालाकोट में घुसकर चंद मिनटों में जैश के आतंकी प्रशिक्षण के ठिकाने को तबाह कर दिया। माना जाता है कि वायु सेना की इस कार्रवाई में ढ़ाई सौ अधिक आतंकी मारे गये। वायु सेना की कार्रवाई के दूसरे दिन पाकिस्तान के द्वारा भारत के सैनिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की गई। पहले से सजग वायु सेना ने न केवल पाकिस्तान को वापस लौटने पर मजबूर किया बल्कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F – 16 को भी मार गिराया। दुर्भाग्यवश जवाबी कार्रवाई के क्रम में भारत का मिग – 21 विमान क्रैश हो गया और विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में जा गिरे। अभिनंदन के बहाने पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी नाजायज मांगों को मंगवाने की कोशिश की लेकिन भारत के सख्त रुख, बेहतरीन कूटनीति और विदेशी दबाव के साथ ही जेनेवा संधि के कारण विंग कमांडर अभिनंदन को उन्हें छोड़ना पड़ा। कार्रवाई के बाद एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय भारत के 21 राजनीतिक दलों द्वारा साझा पत्रकार वार्ता कर बेवजह की प्रतिक्रिया दी गई और चंद दिनों बाद ही विपक्षियों के द्वारा आतंकियों को मारे जाने के सबूत मांगे गये। पुलवामा हमला और विपक्ष की प्रतिक्रिया को केन्द्र में रखकर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के संवाददाता ने देशभर के लोगों से बात की और उनके विचार जाने। प्रस्तुत है कुछ चुनी हुई प्रतिक्रियाएं –

विपक्ष के नेता अपनी भूमिका को भूलाकर जिस प्रकार से सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं उससे दुश्मन देश को भारत पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। विपक्ष के बयानों से शत्रु को लग सकता है कि हमारे देश में एकता नहीं है। राष्ट्र – हित के मुद्दों पर विपक्ष को अपने छद्म राजनीतिक लाभ को दरकिनार कर सरकार व सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए ताकि पाकिस्तानपरस्त आतंकवादी दोबारा भारत की तरफ नजर उठाकर देखने की हिमाकत न कर सके।

- अभिनव पडोंत्रा (जम्मू)

वर्तमान परिदृश्य में श्रेय लेने की राजनीति चल पड़ी है जो बेहद खतरनाक है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हर किसी को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ऊलजुलूल बयानबाजी करने पर उतारू है । सेना को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। जब देश की सत्ता विपक्षियों के हाथों में थी तब उनकी जुबां सिल गई थी । आज उभरते भारत को देखकर उन्हें रास नहीं आ रही है। विश्व का ध्यान भारत की ओर है । विपक्षी पार्टियों को इसकी चिंता सता रही है, क्योंकि भारत जितना आगे बढ़ेगा उनके चुनावी प्रोपगंडे और जनता को लुभाने वाली नीतियां समाप्त हो जायेगी। अरसे बाद भारत को ऐसा नेतृत्व मिला है जो दुश्मन की मांद में जाकर शिकार करने की बात करता है। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को आपसी मनमुटाव भूलाकर एकजुटता दिखाना चाहिए न कि सेना के शौर्य पर शक।

- **चर्वित बालियान** (हरिद्वार, उत्तराखंड)

भारत में आतंकवादी हमला कोई नई बात नहीं है । लगभग 40 सालों से देश आतंकवाद को झेल रहा है। वर्तमान समय में यह एक चेन की तरह काम कर रहा है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कल क्या होगा? भारत के अंदर ही गद्दार बैठे हैं जो खाते तो भारत के हैं लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं। उनलोगों को भारतीय सेना से ज्यादा गद्दार पाकिस्तान की बातों पर विश्वास है। पाकिस्तान ने विंग कमांडर को अंतर – राष्ट्रीय दबाव और जेनेवा संधि के कारण छोड़ा और हमारे देश के गद्दारों ने इसे इमरान खान की दरियादिली करार दे दिया। भारत सरकार को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर सुरक्षा उपायों को सख्ती से अपना चाहिए। वक्त है हम सभी को एकजुट होकर पाकिस्तानियों के मांइड गेम में न फंसकर भारतीय सेना व सरकार के कदमों का सराहना करें।

- **शरूनग्बम ईनाओचा** (इम्फाल, मणिपुर)

विपक्ष का बार – बार भारतीय वायुसेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना कहीं न कहीं उसके स्वार्थ व राष्ट्र को मजबूत न होने देने की इच्छा को दर्शाता है। कोई सत्ता पाने के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि हमारी सेना द्वारा किये गये पराक्रम का बार –बार सबूत मांगे। इस बार 14 फरवरी को वायुसेना के द्वारा किये गये एयर स्ट्राइक का सबूत मांगकर विपक्ष के नेताओं एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें देशहित से कोई लेना – देना नहीं है। एक तरफ वे लोग पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का ढ़ोंग करते हैं वहीं दूसरी ओर साक्षात सेना द्वारा की गई कार्रवाई पर विश्वास नहीं करते। सबूत मांगने वालों को वायुसेना ने यह कहकर करारा जवाब दिया है कि सेना का काम टारगेट हिट करना है न कि मरने वालों की लाशों को गिनना। अगर 26 फरवरी की कार्रवाई में पाकिस्तान को कोई क्षति नहीं हुई है तो उसके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है ? हमने सुना था कि विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को उसके अनछुए कर्तव्य को याद दिलाना होता है लेकिन यहां तो विपक्ष अपनी सेना पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है।

- **ग्रीष्मा त्रिवेदी** (इंदौर, मध्यभारत)

परिषद् गतिविधियां

दिल्ली : एग्रीविजन कार्यशाला के दौरान शोध पत्र का विमोचन करते केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, महामंत्री आशीष चौहान, कृषि अनुसंधान परिषद् के उपमहानिदेशक डॉ. एन. एस. राठौर, निदेशक डॉ. ए. के. सिंह, एग्रीविजन के राष्ट्रीय संयोजक गजेन्द्र तोमर व अन्य

संभाजीनगर(महाराष्ट्र) : छात्र सम्मेलन का उद्घाटन करते महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष हरीभाई बागड़े, अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान व अन्य

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 March, 2019
Date of Publishing: 8 March, 2019

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi

पुलवामा हमले के बाद देश भर में आक्रोश